● वर्ष-3
● अंक-258
रायपुर, शुक्रवार 07 जून 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6›› बैचलरेट पार्टी के लिए तलाश रहे...

18वीं लोस में आंकड़े चौंकाने वाले- संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में 150 देशों से पीछे है भारत

नई दिल्ली. संसदों पर एक वैश्विक डेटाबेस आईपीयू-पारलाइन के आंकड़ों के अनुसार, संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत का प्रदर्शन 150 देशों से भी खराब है। 2024 के लोकसभा चुनावों में 74 महिला सांसद चुनी गईं, जो संसद में कुल सदस्यों की संख्या का 13.6 प्रतिशत थीं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 14 पार्टियों में महिलाएं सांसद चुनी गई हैं, बीजेपी 31 महिला सांसदों के साथ इस सूची में सबसे आगे है। उनके बाद 13 महिला सांसदों के साथ कांग्रेस और 11 महिला सांसदों के साथ टीएमसी हैं।

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) पारलाइन, राष्ट्रीय संसदों पर मई 2024 में एक रैंकिंग प्रकाशित की, जो संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। 2019 में 14.7 प्रतिशत सांसद महिलाएं थीं, जिससे वैश्विक सूचकांक में भारत की रैंकिंग 145 हो गई। 2019 में महिला सांसदों की संख्या भारत में अब तक की सबसे ज्यादा थी. मई 2024 तक, महिला सांसदों की संख्या में गिरावट आई है, जिससे भारत की रैंकिंग गिरकर 150 हो गई है। भारत वैश्विक औसत 26.5 प्रतिशत के साथ-साथ दक्षिण और मध्य एशियाई औसत 19 प्रतिशत महिला सांसदों से पीछे है। भारत संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से आगे है। संसद में 61.3 प्रतिशत महिला सांसदों के साथ रवांडा सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर है। एशिया में भारत के पड़ोसियों की स्थिति भी बेहतर है। पाकिस्तान की रैंकिंग 116, चीन की 89 और नेपाल की 55 है। 2023 में भारत ने महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पारित किया, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा। कम से कम परिसीमन और जनगणना आवश्यकताओं के कारण यह विधेयक 2029 तक अधिनियमित हो जाएगा।

मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली रवाना हुए सभी भाजपा सांसद, संसदीय दल की बैठक में होंगे शामिल

इस बार मंत्रिमंडल में मिलेगा मौकाः साय

रायपुर. संसदीय दल की बैठक में शामिल होने भाजपा के सभी सांसद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ दिल्ली रवाना हुए. डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी दिल्ली रवाना हुए. एयरपोर्ट पर सीएम साय ने कहा, कल दिल्ली में नवनिर्वाचित सांसदों, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है इसीलिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं. इस बार मंत्रिमंडल में हमें मौका तो मिलेगा ही, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एकाधिकार है.

प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे. पूरे देश ने एनडीए पर भरोसा जताकर पूर्ण बहुमत दिया है. इसी विषय पर कल सांसदों की बैठक बुलाई गई है. राहुल गांधी की प्रेसवार्ता पर किरण सिंह देव ने कहा, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोगों ने पूरे देश में भ्रम का वातावरण बनाया. इन लोगों ने संविधान का भ्रम फैलाकर चुनाव परिणाम प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन ये नाकामयाब रहे. इनकी झूठी बातों पर कुछ चुनिंदा लोगों ने भरोसा जताया, लेकिन उनसे कुछ प्रभावित न हो सका. बाकी तो विपक्ष का काम कहना ही होता है.

छत्तीसगढ़ में 10 सीट जीतने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने भरोसा जताया है. जनता के बीच अटूट विश्वास रहा है इसीलिए हमें 10 सीट जीताकर दिया गया है. हम निरंतर मेहनत किए हैं. केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय जो होगा सर्वमान्य होगा.

गौरवशाली पल के बनेंगे साक्षीः साव -शर्मा

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, दिल्ली में बैठेकें होगी. ऐतिहासिक और गौरवशाली पल के साक्षी बनेंगे. 1962 के बाद पहली बार देश में इतिहास लिखा जाएगा. तीसरी बार पीएम मोदी शपथ लेंगे. छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार के साथ काम करेंगे. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, कल महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें शामिल होने सीएम, डिप्टी सीएम और नवनिर्वाचित सांसद जा रहे हैं. बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी. ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बनेंगे. संसदीय दल की बैठक में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, रूपकुमारी चौधरी, कमलेश जांगड़े, महेश कश्यप, तोखन साहू, चिंतामणि महाराज शामिल होंगे.

शेयर बाजार को लेकर राहुल ने लगाया घोटाले का आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए 4 जून के शेयर बाजार दुर्घटना की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी सवाल किया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित शीर्ष भाजपा नेताओं ने चुनाव परिणामों की घोषणा से कुछ दिन पहले शेयर बाजार के बारे में टिप्पणियां क्यों कीं। राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार हमने देखा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने निवेशकों को निवेश करने की सलाह क्यों दी। उन्होंने कहा कि 'फर्जी' एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में तेजी आई और फिर चार जून को गिरावट आई। राहुल ने साफ तौर पर कहा कि खुदरा निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.

निवेशकों को डराने और गुमराह करने की रच रहे साजिश

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सबसे बड़ा शेयर बाजार घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग की। हालांकि, इसी को लेकर भाजपा की ओर से पलटवार किया गया है। बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबर नहीं पाए हैं। अब वह बाजार के निवेशकों को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। गोयल ने साफ तौर पर कहा कि आज राहुल गांधी ने प्रेसवार्ता कर जो भाजपा और हमारे नेताओं पर अनाप-शनाप आरोप लगाए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से राहुल गांधी जी उबर नहीं पाए हैं। अब राहुल गांधी मार्केट के इंवेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आज पूरी दुनिया, भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार करती है। मोदी ने देश को आश्वस्त किया है कि उनके तीसरे टर्म में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

मोदी सरकार में पांच कैबिनेट पद चाहती है टीडीपी

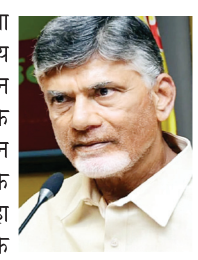

नई दिल्ली। गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) संसदीय दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से पार्टी नेताओं को पांच और केंद्र में उसकी सहयोगी जन सेना को दो कैबिनेट सीटें आवंटित करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। पार्टी नेताओं ने गुरुवार को यह बात कही। हाल ही में संपन्न आम चुनाव में नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी ने 25 लोकसभा सीटों में से 16, जन सेना ने दो और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के हिस्से के रूप में भाजपा ने तीन सीटें जीतीं। टीडीपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की भी मांग करेगी क्योंकि 2014 में राज्य के विभाजन के कारण उसने अपना सबसे बड़ा राजस्व स्रोत - हैदराबाद - खो दिया है। पार्टी के एक सांसद ने कहा कि मंत्री पद के लिए हमारा अनुरोध उस विशेष पैकेज पर आधारित है जिसका वादा पुनर्गठन के समय आंध्र प्रदेश को किया गया था। विशेष दर्जे की आवश्यकता मूल रूप से राज्य में प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए केंद्रीय अनुदान है। विजयवाड़ा के बाहरी इलाके उंदावल्ली में नायडू के आवास पर हुई बैठक में, पार्टी ने पूरे कार्यकाल के दौरान एनडीए का समर्थन करने का वादा किया, भले ही भाजपा अपने विधायक दल के नेता के रूप में किसे चुने। प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश के पिछड़े सात जिलों के लिए अनुदान है - तीन उत्तर आंध्र से और चार रायलसीमा क्षेत्र से।

प्रमुख समाचार

जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार बनाने का मौका जल्द मिलेगा,

श्रीनगर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का चुनाव लंबित है, जब हम 12 मार्च को वहां गए थे तभी हमने संकेत दे दिया था कि हम सही समय पर यह करेंगे... हम जल्दी से जल्दी वहां लोगों को अपनी सरकार बनाने और अपने हिसाब से अपने जनप्रतिनिधि चुनने का मौका देंगे। पिछले 20-22 सालों से ईवीएम सही नतीजे दिखाती आ रही है। वह बहुत भरोसेमंद है, वह हर प्रकार से तटस्त हो चुकी है और अपना काम करती है। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने एक बयान में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदान 65.79 प्रतिशत दर्ज किया गया। राज्यों में असम में सबसे अधिक 81.56 प्रतिशत मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में सभी राज्यों में सबसे कम 56.19 प्रतिशत मतदान हुआ। मानक अभ्यास के अनुसार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त विवरणों को अंतिम रूप देने के बाद डाक वोटों की संख्या और सकल मतदाता मतदान की विस्तृत सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

एयरपोर्ट पर महिला गार्ड ने कंगना को मारा थप्पड़

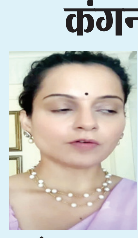

चंडीगढ़। बॉलीवुड अदाकारा और हिमाचल के मंडी सीट से भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के एक गार्ड ने कथित तौर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर उनकी टिप्पणी को लेकर थप्पड़ मारा। अभिनेत्री ने इस घटना के लिए कुलविंदर कौर के रूप में पहचाने गई गार्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हाल ही में लोकसभा चुनाव जीतने वाली कंगना रनौत घटना के समय दिल्ली जा रही थीं। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मंडी से सांसद-चुनाव को सुरक्षा जांच के दौरान अपना फोन ट्रे में रखने से इनकार करने पर एक सुरक्षाकर्मी को धक्का देने के लिए थप्पड़ मारा गया था। कंगना रनौत दोपहर 3 बजे विस्तारा की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुईं। यह घटना रनौत के हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद हुई। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता ने कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों से हराया। राजनीतिक नेता के रूप में अपने पहले लोकसभा चुनाव में रनौत को 5,37,022 वोट मिले।

अग्नीपथ योजनाः सरकार गठन से पहले ही साथी दलों ने उठाई समीक्षा करने की मांग

नई दिल्ली। 18वें लोकसभा चुनावों के दौरान अग्निपथ योजना एक अहम मुद्दा बनी रही। सेना में भर्ती की ये नई स्कीम लगातार चर्चा में बनी रही। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में दावा किया था कि सत्ता में आने पर अग्नीपथ स्कीम को ही हटा दिया जाएगा। इसकी जगह कांग्रेस ने नई योजना लाने का वादा भी किया था। चुनावों के दौरान इस योजना को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी भी हमलावर रहे थे। माना जा रहा है कि एनडीए को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी जैसे राज्यों में कम सीटें मिली है जिसका प्रमुख कारण अग्नीपथ योजना भी रही है। इसे लेकर युवाओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वर्ष 2019 के मुकाबले वोट शेयर में भी गिरावट आई है। वहीं इस योजना के विरोध में सरकार के गठन से पहले ही एनडीए का समर्थन कर रहे दलों ने बोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में संभावना है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार को इस योजना पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। वर्ष 2022 में संसद में मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना को लागू किया था, जिसके बाद युवाओं की नाराजगी का सामना उसे करना पड़ा था।

भाजपा में सेंध लगाने की कोशिश में ममता बनर्जी

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी के तीन सांसद पार्टी के संपर्क में हैं। यह घटनाक्रम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ पक्ष द्वारा एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों को धता बताते हुए बंगाल के किले पर अपना कब्जा बनाए रखने के दो दिन बाद आया है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि भाजपा ने तृणमूल के दावों को खारिज कर दिया है और उन्हें फर्जी करार दिया है। बंगाल लोकसभा चुनाव के सभी सात चरणों में मतदान हुआ, वहां भाजपा की ओर झुकाव की उम्मीद थी। पूर्वी राज्य में अपनी अधिकांश रैलियों में, नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वास्तव में भविष्यवाणी की थी कि राज्य में भगवा पक्ष को 35 लोकसभा सीटें मिलेंगी। अधिकांश सर्वेक्षणकर्ताओं ने बंगाल में भाजपा को भारी लाभ मिलने की भविष्यवाणी की है, जिसमें भाजपा को 26-31 सीटें और तृणमूल कांग्रेस को 11 से 14 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालाँकि, तृणमूल कांग्रेस ने एग्जिट पोल के अनुमानों को ध्वस्त कर दिया और मोदी-शाह लहर को सीमित कर दिया।

नीतीश ही हैं बिहार एनडीए के लीडर, सम्राट चौधरी

नई दिल्ली। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि एनडीए अगला बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार के नेतृत्व की भी तारीफ की है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जद (यू) ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 पर विजयी हुई। यह राज्य में भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (एचएएम) के साथ गठबंधन में है। केंद्र में एनडीए सरकार के गठन के लिए कुमार का समर्थन महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि भाजपा अपने दम पर लोकसभा में बहुमत हासिल करने में विफल रही है। देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि में, सम्राट चौधरी का यह बयान महत्व रखता है कि एनडीए राज्य में 2025 का विधानसभा चुनाव कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में बीजेपी-जेडीयू-चिराग महागठबंधन अजेय है। अगर वे साथ मिलकर लड़ेंगे तो बहुमत का आंकड़ा पार कर जायेंगे। बिहार में जीत के लिए नीतीश कुमार जरूरी हैं।

बस्तर संभाग में भाजपा की जीत- मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन पर बस्तर की जनता ने जताया पूरा भरोसा

मुख्यमंत्री साय के नक्सल विरोधी अभियान पर जनता की मुहर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में भाजपा ने प्रदेश की ग्यारह में से दस सीटों पर शानदार जीत हासिल की। कोरबा सीट में मामूली अंतर से हुई हार को छोड़ दें तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक भाजपा का परचम लहराया और पांच साल बाद बस्तर की सीट फिर से भाजपा के कब्जे में आई। बस्तर संभाग के बस्तर और कांकेर में हुई जीत विष्णु देव साय के सुशासन ही नहीं बल्कि नक्सलवाद के विरुद्ध उनके महाभियान पर भी मुहर लगाती है। जनता का संदेश भी स्पष्ट है कि वो इस लड़ाई में साय सरकार के साथ है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव के तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी यहाँ के मतदाताओं ने भाजपा पर अपना पूरा भरोसा जताया और दोनों सीटें भाजपा की झोली में डाली।

नक्सलवाद पर करारा प्रहार - छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर में नक्सलवाद के उन्मूलन पर लगातार रूचि दिखाई। जिसका परिणाम है कि पिछले पांच महीनों में लगभग 120 नक्सली मारे गए, 400 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और लगभग 200 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। नक्सलियों के खिलाफ इस कार्रवाई से बस्तर की जनता का सरकार के प्रति गहरा विश्वास बढ़ा और यहाँ भाजपा की जीत पर उसकी मुहर लगी है। बस्तर वासियों को पूरा भरोसा है कि सीएम साय की अगुवाई में यह संभाग नक्सलमुक्त होकर रहेगा।

मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन पर बस्तर की जनता ने लगाई मुहर - मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटियों पर काम करना शुरू किया। किसानों को धान का बकाया बोनस, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, महतारी वंदन योजना के तहत महतारियों के खाते में

हर महीने एक-एक हजार की राशि जारी करना, 3100 रूपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 5500 रूपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी, रामलला दर्शन योजना की शुरुआत सभी कार्यों को मात्र सौ दिनों में पूरा किया। जिससे कि बस्तर की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी और विष्णु सरकार पर बढ़ा और आज बस्तर में भाजपा के पक्ष में परिणाम यहाँ के जनता की भाजपा के प्रति विश्वास पर मुहर है। श्री साय ने बस्तर की अपनी हर सभाओं में चुनाव के बाद चरण पादुका योजना को शुरू करने की भी बात कही।

नियद नेल्लानार योजना ने दिलाई निर्णायक बढ़त - मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही विष्णु देव साय ने कहा था कि - बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के विकास पर हमारी उनका विशेष ध्यान होगा। जिस पर तत्काल अमल करते हुए श्री साय ने बस्तर के विकास के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की। जिसके अंतर्गत क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांवों में सड़क, नाली, पानी, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, राशन दूकान बनाने का काम हुआ। गांव के विकास के लिए सरकार के इस महती कार्य को देखते हुए ग्रामीणों का, आदिवासियों का सरकार पर और विश्वास बढ़ा। इसके साथ ही बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा कैंप खोले गए, जो ग्रामीणों के लिए सहायता केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। सीएम साय के इस कार्य पर ही जनता की मुहर लगी और भाजपा ने जीत हासिल की।

मतांतरण पर सीएम साय का कड़ा रिएक्शन - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मतांतरण पर कड़ा रिएक्शन रहा है। वे शुरू से कहते आ रहे हैं कि आदिवासियों का मतांतरण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। आदिवासी सबसे बड़े हिन्दू हैं अगर किसी ने इनकी एकता पर खलल डालने की कोशिश की तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री साय ने मतांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने की भी बात कही। इसका सकारात्मक असर बस्तर संभाग के आदिवासियों पर हुआ और उन्होंने सीएम साय की बातों पर विश्वास कर भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान किया।

सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य ने दिलाई जीत - छत्तीसगढ़ में भाजपा के तीन बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सत्ता और संगठन के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित करने में महारथ है। बिना संगठन के किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता ये उनको भलीभांति पता है। श्री साय ने बस्तर संभाग से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष, सभी मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी और खुद भी कार्यकर्ता सम्मेलन, जनसभा और रोड शो कर जमकर पसीना बहाया। उन्होंने अपनी हर सभा में बस्तर में परिवर्तन की बात कही, जिसने कार्यकर्ताओं के साथ-साथ जनता में भी जोश भरा। जिसका परिणाम है कि सत्ता और संगठन के बीच आपसी तालमेल से बस्तर में परिवर्तन हुआ और भाजपा ने जीत हासिल की।

ग्रामीणों के राशन में कटौती कर कोटेदार भर रहे अपना पेट

किराना दुकान से राशन खरीदने के लिए मजबूर हितग्राही

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शासन की महत्वाकांक्षी योजना पर कैसे पलीता लगाया जा रहा है, इसका नजारा देखने को मिला है। गरीबों को मुफ्त में मिलने वाले राशन पर डाका डाला जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला राशन ग्रामीणों को कम तो कईयों को महीनों से नहीं मिला है। अलाम यह है कि ग्रामीण करें तो करें क्या। वे बाजार से चावल खरीदकर खाने को मजबूर हैं। वहीं, प्रशासन मामले में जल्द कार्रवाई किये जाने की बात कह रहा है।

पेंड्रा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जाटादेवरी के आश्रित गांव हर्राडीह में रहने वाले ग्रामीणों को पिछले अप्रैल माह में शासन के द्वारा एक साथ 70 किलो चावल देना था, लेकिन गांव में राशन दुकान का संचालन करने वाली वैष्णवी महिला स्वं. सहायता समूह के द्वारा गरीब हितग्राहियों को 70 किलो चावल नहीं दिया गया। राशन लेने पहुंचे ग्रामीणों को सेल्समेन के द्वारा सिर्फ 50 किलो चावल देते हुए कहा दिया गया कि उनके नाम से उनके पास सिर्फ 50 किलो चावल अभी आया है। जबकि 20 किलो बचा चावल उन्हें बाद में मिलेगा।

हितग्राहियों के द्वारा बचा हुआ 20 किलोग्राम चावल के लिए कई बार राशन दुकान जाने के बाद भी उन्हें उनका बचा हुआ चावल नहीं दिया गया। बस आज मिलेगा कल मिल जाएगा कहकर टाल दिया जाता। यही नहीं कुछ हितग्राहियों का कहना है कि उन्हें राशन दुकान संचालक के द्वारा पिछले 3 से 4 माह का न चावल न ही शक्कर न ही चना मिला है। बार-बार दुकान जाने के बाद भी उन्हें राशन नहीं मिला, जबकि राशन दुकान संचालक के द्वारा बड़े ही चालाकी से गरीब हितग्राहियों के राशन कार्ड में राशन दिया जाना बतालाकर माह का राशन चढ़ा दिया जाता रहा।

कुछ ग्रामीणों की मानें तो उन्हें तो 4-4 माह होने के बाद भी शक्कर और चना दुकानदार के द्वारा नहीं दिया गया। ग्रामीणों को राशन नहीं मिलने के चलते काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। स्थिति यह है कि उन्हें अपना और अपने परिवार के लोगों का पेट भरने के लिए गांव के किराना दुकानों से चावल खरीदना पड़ रहा है। वहीं, ग्रामीणों और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की मानें तो मामले की शिकायत उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को भी की गई, लेकिन वहां से भी कोई समाधान नही हुआ।

खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल ने बताया कि मामले की शिकायत के बाद उनके द्वारा संबंधित खाद्य अधिकारी को मौके पर भेजकर जांच करवाई गई है। मामले में ग्रामीणों की शिकायत भी सही पाई गई है। जांच प्रतिवेदन बनाकर अग्रिम कार्रवाई के लिए अमित बेक एसडीएम पेंड्रा रोड को दे दिया गया है। जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी।।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीब हितग्राहियों को मुफ्त में मिलने वाले राशन में हेराफेरी का यह कोई नया मामला नहीं है। हेराफेरी करने वाले दुकान संचालकों के द्वारा ऐसा करना कहीं न कहीं इनके ऊपर होने वाली कार्रवाई का डर बिल्कुल भी नहीं होता, जिसके चलते ये लोग गरीबों के हक में डाका डालने में नहीं चूकते। जरूरत है ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

एसपी ने लौटाए 45 लाख के गुम 230 मोबाईल

कोंड़ागांव। जिले में साइबर सेल तथा थाना, चौकी को गुम मोबाइलों के संबंध में लगातार आवेदन प्राप्त हो रहा हैं। पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार द्वारा साइबर सेल की टीम को उनके दैनिक कार्यो के साथ गुम हुए मोबाइलों के खोजबीन की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। एडिशनल एसपी रूपेश डांडे तथा नोडल अधिकारी सायबर सेल सतीश कुमार भार्गव के मार्गदर्शन में सायबर सेल टीम द्वारा लगातार गुम, चोरी की पतासाजी में लगे हुये हैं, जिससे विगत 20 दिनों में साइबर सेल की टीम को 230 गुम हुए मोबाइलों को रिकवर करने में सफलता मिली है। जिसका वर्तमान बाजार मूल्य करीब लगभग 45 लाख रुपए है। सायबर सेल द्वारा रिकवर किए गए मोबाइल छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के अलावा सीमावर्ती राज्यों से रिकवर किया गया है। रिकवर किए गए मोबाइलों में कई महंगे सेट वनप्लस, वीवो, रेडमी, सैमसंग, रियलमी, के महंगे सेट भी है। मोबाइल लौटाते हुये उनके मलिकों को मोबाइल संभाल कर रखने और दोबारा नहीं गुमाने कहा गया और मोबाइल उपयोग के पूर्व उन्हें एक बार फार्मेट कर उपयोग करने की सलाह दी गई। कई मोबाइल स्वामी ने बताया कि वे अपने मोबाइल वापसी की उम्मीद खो चुके थे, वे उन्हें दोबारा पाकर कोण्डगांव पुलिस को धन्यवाद देकर जा रहे हैं। गुम हुए मोबाइलों को ट्रेस करने और रिकव्हर करने हेतु कोण्डागांव साइबर सेल द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।

बेमेतरा में अवैध हथियार के कारोबार का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा। जिले में अवैध रूप से पिस्टल की खरीदी-बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों ने लूट की झूठी घटना बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। आरोपियो के पास से 70 हजार नगद, 2 पिस्टल, 6 राउंड के 2 मैग्जीन, 1 कार, 2 बाइक और 03 मोबाईल फोन जब्त किए हैं। बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है।

एसडीओपी मनोज कुमार तिर्की ने बताया, 3 जून को पुलिस को खबर मिली कि कंतेली के पास अज्ञात आरोपियों ने एक व्यक्ति के पैर में गोली मारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू किया। लेकिन पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि तीन लोगों ने मिलकर एक बाइक सवार को गोली मारी और पैसे भी नहीं लूटे। दूसरी बात यह भी थी कि गोली पैर पर ही क्यों मारी।

एसडीओपी मनोज कुमार तिकी ने कहा पुलिस ने पहले नाकेबंदी की और गोली लगने वाले घायल से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि वह बेमेतरा के दिनेश चंद्र शर्मा के पास कट्टा सप्लाई करने आया था। इसी दरमियान ट्रायल के दौरान उन्होंने दो फायर हवा में किया और तीसरी फायर धोखे से उनके पैर में ही लग गई। घटना को छुपाने के लिए तस्लीम चौधरी ने पुलिस को लूट किस्सा सुनाया था। जिसके बाद यह खुलासा हुआ है।

बेमेतरा पुलिस ने अजय कुमार कश्यप (21) निवासी बड़ौत, जिला बागपत (यूपी), जो उप जेल बेमेतरा के सामने रहता है और दूसरा आरोपी दिनेश चंद्र शर्मा (41) निवासी वार्ड नं। 16 मुक्तीधाम के सामने नयापारा बेमेतरा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। घायल आरोपी तस्लीम चौधरी का जिला अस्पताल बेमेतरा में ईलाज जारी है। वहीं एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम रवाना की गई है।

कोरबा के विकास के लिए कोई राजनीति नहीं होगी: ज्योत्सना

कोरबा। कोरबा के विकास के लिए कोई राजनीति नहीं होगी, सभी का सहयोग लेकर हम सामूहिक प्रयास से सुविधाओं और विकास से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। संसदीय सीट की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए पूरी इच्छा शक्ति से काम करेंगे। संसदीय सीट की जनता ने भाजपा की राष्ट्रीय नेत्री को पराजित कर मुझे दूसरी बार सांसद के रूप में सेवा करने का अवसर दिया है। वे शोर मचा रहे थे और हम अपना धर्म निभाते हुए सेवा कार्य में लगे रहे। उक्त बातें छत्तीसगढ़ से निर्वाचित एकमात्र कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहीं।

उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षा के अनुरूप यहां बिसाहू दास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज की स्थापना में अपनी भूमिका निआई। अब इसके संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा। जल्द ही हम कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक करेंगे। कोरबा रेलवे स्टेशन के उन्नयन के काम में तेजी लाई जाएगी, गेवरा रोड स्टेशन में सुविधाओं का विस्तार करेंगे। यात्री ट्रेन समय पर चले, बंद ट्रेनों को शुरू करने, कोयला राखड़ के प्रदूषण से कोरबा को मुक्त कराने, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था सुचारू करने के लिए काम करेंगे। सड़कों के कार्य मेरे प्रयासों से शुरू हुए हैं, जिन्हें पूरा कराएंगे। कोरबा की ट्रैफिक संबंधी समस्या दूर करनी होगी। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना होगा। फाटकों के कारण यातायात में दिक्कत आ रही है। प्रस्तावित अंडर ब्रिज के काम में तेजी लाई जाएगी। मल्टीलेवल पार्किंग को उपयोग में लाया जाएगा। हसदेव नदी से कोरबा को वैकल्पिक मार्ग से जोड़ा जाएगा ताकि पावर हाउस रोड में ट्रैफिक की समस्या दूर हो सके। नया ट्रांसपोर्ट नगर जल्दी बने इसका प्रयास करेंगे। साथ ही 1300 मेगावाट का पॉवर प्लांट जल्द शुरू करने की कोशिश होगी। बांकीमोंगरा, जटगा, उमरेली व रामपुर में स्वीकृत कॉलेजों के लिए भवन की कमी को दूर करेंगे। भू विस्थापितों व कामगारों की समस्याओं का हल निकालेंगे।

नारायणपुर के इरकभट्टी कैंप में नक्सली हमला

4 बीजीएल दागे एक फटा, कैम्प और जवान सुरक्षित

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में नक्सलियों का आतंक जारी है। बुधवार को नक्सलियों ने कोहकमेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत नव स्थापित इरकभट्टी कैम्प में बीजीएल से हमला किया और घने जंगल की आड़ में भाग निकले। हमले में कैम्प और जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने हमले की पुष्टि की है।

नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने बताया, बुधवार को नक्सलियों ने कोहकमेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत नव स्थापित इरकभट्टी कैम्प में 4 देशी बीजीएल दागा, जिनमें से केवल 1 बीजीएल फटा है। हमले के बाद कैम्प में तैनात जवानों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों पर जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगलों की आड़ लेकर भाग निकले। इस हमले में कैम्प और जवानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

आईजी सुंदरराज पी ने कहा नारायणपुर जिले में नवीन कैंप के विस्तार, लगातार बढ़ते विकास कार्यों और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई से नक्सली बौखलाए हुए हैं। इसलिए कैम्प में हमला कर रहे हैं। लेकिन बस्तर में पुलिस के जवान नक्सली मोर्चे पर डटकर उनका सामना कर रहे हैं। कैंप एवं सभी जवान सुरक्षित हैं।

नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ में लगातार नक्सल गतिविधियां देखने को मिल रही है। बीते दिनों इस क्षेत्र में पुलिस जवानों ने नक्सल विरोधी ऑपरेशन करके नक्सलियों पर हमला किया था। क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास कार्यों से भी नक्सली बौखलाए हुए हैं। इरकभट्टी से कुतुल तक पक्की सड़क व सभी नालों में पुल- पुलिया का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही नियद नेल्लानार योजना के तहत सभी कैंपो के करीब 5 गांवों को सभी सरकारी योजनाओं का प्राथमिकता के साथ लाभ मिल रहा है, जिससे नक्सल संगठन कमजोर हो रहा है। इससे बौखलाए नक्सली अब जवानों को निशाना बनाने की फिराक में हैं।

पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनों ने की वट सावित्री की पूजा

जगदलपुर। वट सावित्री व्रत के चलते गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हुए बरगद पेड़ की पूजा की और आशीर्वाद लिया। बताया जाता है कि यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, सावित्री नाम की महिला ने अपने सुहाग यानि पति के प्राणों की रक्षा के लिए वट वृक्ष के नीचे यमराज की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान की आयु बढ़ा दी। सुहागन स्त्रियां सावित्री की तरह वटवृक्ष के नीचे पूजा करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं।

हिंदू धर्म में महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना में कई व्रत रखती हैं। इनमें एक प्रमुख व्रत है वट सावित्री का व्रत। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रखा जाता है। इस वर्ष यह व्रत गुरुवार को था। इस दिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। महिलाएं देवी सावित्री के पति प्रेम और पतिव्रत धर्म को स्मरण कर अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं।

वट सावित्री व्रत सती सावित्री से जुड़ा है। सावित्री की कथा के अनुसार देवी सावित्री ने पति के प्राणों की रक्षा के लिए विधि के विधान को बदल दिया था। अपने सतीत्व और कठोर तपस्या से सावित्री ने यमराज को अपने पति सत्यवान के प्राण लौटाने पर विवश कर दिया था। यमराज ने वटवृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण लौटाए थे और वरदान भी दिया था कि जो सुहागिनें वटवृक्ष की पूजा करेंगी, उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलेगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

विधायक टेकाम जनदर्शन लगाकर करेंगे मुलाकात

कोंड़ागांव। जिले के केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम लोकसभा चुनाव के आचार संहिता खत्म होने के बाद अपने कार्यलय में प्रत्येक गुरुवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अपने निवास में जनदर्शन लगाकर केशकाल विधानसभा की जनता से मुलाकात करेंगे उनकी समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करेंगे। विधायक टेकाम ने सभी मण्डल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री व कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि केशकाल विधानसभा क्षेत्र की जनता के समस्याओं को लेकर अब परेशान न होना पड़े इसलिए यह सूचना प्रसारित करने में सहयोग करें ताकि केशकाल विधानसभा की जनता के समस्याओं का त्वरित निराकरण कराने में हम सफल हो सकें। चूंकि लोकसभा चुनाव के वयस्तता के चलते क्षेत्र में रुकी हुई सभी कार्यों को गति मिलेगा व जनता को छोटी समस्याओं को लेकर ज्यादा मुश्किलों का सामना नही करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के परिणम के बाद कोंडागांव जिले के पूर्व कलेक्टर एवं केशकाल के विधायक टेकाम जनदर्शन लगाने का निर्णय लिया है।

मॉर्निंग वॉक पर निकले भाजपा नेता पर हमला

बिलासपुर। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अर्जुन भोजवानी पर हमला हुआ है। इस हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बीजेपी नेता को जमीन पर गिरा देता है और उनके सिर पर पत्थर से हमला कर देता है। जिसमें बीजेपी नेता लहूलुहान हो जाते हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार, हर दिन की तरह आज सुबह भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अर्जुन भोजवानी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे। तभी कोतवाली थाना क्षेत्र के रिवर व्यू के पास के बदमाश से किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गया। इस दौरान बदमाश ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और सिर पर पत्थर से कई बार वार किया। इस घटना में अर्जुन भोजवानी घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे लोग तमाशा देखते रहे। भाजपा नेता ने मामले की शिकायत पुलिस से की है।

जमीन विवाद, कोटवार ने दो महिलाओं को ट्रैक्टर से कुचला

तखतपुर। जमीन विवाद को लेकर ट्रैक्टर से दो आदिवासी महिला को कुचलने का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर ग्रामीण आदिवासियों ने आज एसडीएम दफ्तर और थाने का घेराव किया। तत्काल प्रभाव से आरोपी कोटवार को कोटवारी पद से हटाने की जिद पर ग्रामीण अड़े हैं। एसडीएम दफ्तर में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जारी है। बता दें कि बीते दिनों ग्राम बीजा में खेत जुताई को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान कोटवार ने ग्रामीण आदिवासी अल्का और बाल्का को ट्रैक्टर से कुचल दिया था। इससे दोनों आदिवासी महिलाओं को गंभीर चोटें आई थी। इस मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय और थाने का घेराव किया। कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे।

डॉक्टर सहित सात कर्मचारियों पर गिरी गाज

बिलासपुर। बिलासपुर ग्रामीण इलाके की शासकीय अस्पताल में ताला बंद पाए जाने पर एक डॉक्टर सहित कुल सात स्वास्थ्य कर्मचारियों के एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। मस्तुरी ब्लॉक के पीएचसी ओखर में 25 मई को ऑफिस टाइम में अस्पताल तालाबंद पाया गया। बड़ी संख्या में मरीज डॉक्टरों के आने का इंतजार कर रहे थे। कलेक्टर को जानकारी मिलने पर नाराजगी जताई और कार्रवाई के निर्देश दिए। बीएमओ मस्तुरी द्वारा 28 मई को उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया। उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक दिन का वेतन काटने की सजा सुनाई गई है। उन्हें भविष्य में समय पर अस्पताल पहुंचकर मरीजों का इलाज करने की चेतावनी भी दी गई है। जिन डॉक्टर और कर्मचारियों के वेतन काटा जा रहा है, उनमें चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिवशंकर नागेशी, आरएमए गोविंद प्रसाद बंजारे, नेत्र सहायक भागीरथी बंजारे, फार्मा ग्रेड 2 देवेंद्र बंजारा, स्टॉफ नर्स विभव कच्छप, स्टाफ नर्स शिवानी पांडेय तथा सहायक ग्रेड 3 नरेंद्र कुमार राठौर शामिल हैं।

नशे के अवैध कारोबार का भंडाफोड़, दो तस्कर गिरफ्तार

दुर्ग। भिलाई के नेवई थाना क्षेत्र की पुलिस को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नेवई थाना क्षेत्र से नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 14 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा और एक कार जब्त किया है। शहर एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया, विशेष सूत्रों से पता चला कि कोमना नुआपाड़ा ओडिशा निवासी जीना तांडी (35) और व्यासदेव मांझी ओडिशा (38) एक महंगी कार में छुपाकर मादक पदार्थ गांजा भिलाई लाए हैं। लोकल एरिया में सप्लाई करने के लिए विवेकानंद यूनिवसिटी के पास नेवई बस्ती में उनके मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर दोनों तस्करों को पकड़ लिया है। सुखनंदन राठौर ने कहा मुखबिर की सूचना पर नेवई बस्ती से दो लोगों को पकड़ा गया है। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 19 पैकेट में लगभग 14 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला। दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर परसा ईस्ट कांता बासन खदान में रोपे गए 25000 पौधे

- **अदाणी ग्रुप ने 2030 तक 86 लाख पेड़ लगाने का रखा है लक्ष्य**

अंबिकापुर। अदाणी समूह ने 2030 तक 10 करोड़ पेड़ और समूह के प्राकृतिक संसाधन विभाग ने अगले छह वर्षों में 86 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के परिप्रेक्ष्य में सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील में कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राज्य की एक मात्र 5 स्टार रेटिंग की परसा ईस्ट कांता बासन (पीईकेबी) खदान ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 25000 पौधे लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एक कदम और आगे बढ़ाया है। इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने में 800 प्रतिभागियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) की पीईकेबी खदान में कोयला निकाले जा चुकी भूमि अर्थात रिक्लेमेड भूमि में पिछले 10 सालों 11।50 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके हे, जो भारत के खनन उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम है।

खास बात यह है कि आरआरवीयूवीएनएल और उसके द्वारा चुने गए खदान संचालक अदाणी नेचुरल रिसोर्सेज के बागवानी विभाग ने जंगली पेड़ साल की नर्सरी बनाने में भी बड़ी सफलता पाई है। इसके साथ ही पिछले 10 वर्षों में 82,000 से ज्यादा साल के पौधे को विकसित करने की एक मुश्किल प्रक्रिया से साल के वृक्षों का सफल रोपण कर एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है।

बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीईकेबी खदान पर प्रशासनिक भवन से हनुमान वाटिका तक पैदल मार्च निकाला गया और उसके बाद विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। वृक्षारोपण अभियान में खदान के पास 25 हजार पौधे रोपे गए। इन पौधों को पानी और अन्य पोषण के लिए अध्यातन व्यवस्था भी की गई है । जबकि इसकी शुरूआत 1 से 4 जून तक निबंध लेखन प्रतियोगिता सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें परसा, साल्ही, घाटबर्रा, फतेहपुर, बासेन और तारा गांव से 295 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। यहां का बागवानी विभाग खदान क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण उसके सतत विकास और जैव विविधता सुनिश्चित करने के लिए मियावाकी और गोटी एयर लेयरिंग जैसी नवीन तकनीकों का उपयोग करती है।

आरआरवीयूएनएल के एमडीओ अदाणी इंटरप्राइजेस लिमिटेड (एईएल) के बागवानी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने न सिर्फ़ साल के हजारों पौधों की नर्सरी तैयार की बल्कि इन्हें खदान के रिक्लेमेशन विस्तार में उगाकर एक नये जंगल का रूप भी दिया है। खदान ने 1100 से ज्यादा एकड़ भूमि में साल वृक्षों का नया जंगल विकसित किया है जहां समय के साथ लगभग 20 से 30 फुट ऊँचे वृक्षों में तब्दील हो गए हैं। इस साल 82 हजार साल के पौधे उगाने का लक्ष्य रखा गया है।

खदान के उद्यान विभाग के प्रभारी राजकुमार पाण्डेय ने बताया कि, खदान ने वन विभाग के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में 2 लाख 12 हजार से अधिक पेड़ लगाए थे। वहीं खदान ने 9 हजार से अधिक साल वृक्षों का सफल प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लांटेशन) भी किया है। खदान में एक आधुनिक नर्सरी भी बनाई गई है, जहां वर्ष के किसी भी समय इस नर्सरी में लगभग 3 लाख पौधे वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध रहते हैं।

पांच राज्यों में विभिन्न स्थलों पर अदाणी नेचुरल रिसोर्सेज की खनन परियोजना की टीमों ने 50,000 से अधिक फलदार और देशी पौधे लगाए और वितरित किए, जो हरित भविष्य के पोषण के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

खदान का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में और अधिक पेड़ लगाकर एक हरित छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जाए। जिस जापानी मियावाकी तकनीक से घने जंगल उगाने का कार्य किया जा रहा है, उसके माध्यम से 55 से 60 पौधे इस क्षेत्र के मूल प्रजाति के लगाए जाते हैं ताकि यह हमेशा हरे-भरे रहें और एक सघन जंगल बन जाए। जहां सामान्य तरीके से वृक्षारोपण में एक हेक्टेयर में 2500 पेड़ लगाए जाते हैं, वहीं इस तकनीक से एक हेक्टेयर में 30000 से 35000 पेड़ लगाए जाते हैं।

बचेली में नपा अध्यक्ष के साथ पार्षदों ने किया वृक्षारोपण

बचेली। नगर पालिका परिषद द्वारा वार्ड दस में निर्माणाधीन पार्क में अध्यक्ष पूजा साव और पार्षदों ने बुधवार को वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के दौरान पार्षद फिरोज नवाब, रीना दुर्गा, अप्पू कुंजाम, अर्चना उइके, ब्रह्मा सुननी, बिन्नी उपस्थित थे। इस दौरान वार्ड वासी निलेश पटले, आनंद मौर्य, सम्मद्दार, खुशी कुंडू, शालू सपना, अलका समाद्दार ने भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर पार्षद फिरोज नवाब ने कहा की पौधा लगाना आसान पर पौधे का देखभाल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमे वृक्ष लगाना महत्वपूर्ण हो सकता है।

संक्षिप्त समाचार

मोतीलाल और भूलन सिंह मरावी रोगी पशु कल्याण समिति के सदस्य मनोनीत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू एवं प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी को राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय रायपुर के रोगी पशु कल्याण समिति का सदस्य मनोनीत किया है। यह समिति पशुधन के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करती है। जिसका उद्देश्य पशुधन को उसका सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का हक प्रदान करता है।

विधायक मिश्रा हर महीने के 5 तारीख को करेंगे जनसमस्याओं का निराकरण

रायपुर। रायपुर जिला कार्यालय एकात्म परिसर में विधायक पुरन्दर मिश्रा हर महीने के 5 तारीख को 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनदर्शन लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे जिसका प्रारंभ 5 जून को हो गया। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए विधायक मिश्रा ने आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरा उतरना ही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी।

बघेल आज मोहला-मानपुर और खुज्जी-डोंगरगांव क्षेत्र में निकालेंगे आभार रैली

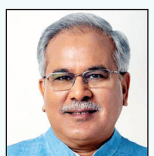

राजनांदगांव। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी को सहयोग करने के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कल से दौरे की शुरूआत करेंगे। बघेल मोहला-मानपुर में कल 7 जून को कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से भेंटकर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करेंगे। इसके बाद वह दोपहर को खुज्जी विधानसभा के कुमर्दा और शाम को डोंगरगांव पहुंचेंगे। 8 जून को राजनांदगांव विधानसभा के बाद खैरागढ़, डोंगरगढ़ क्षेत्र में आभार रैली करेंगे। 9 जून को कवर्धा और पंडरिया विधानसभा में आभार के लिए दौरा होगा।

छत्तीसगढ़ में अब 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी दो बार

रायपुर/जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दो बार होगी। दो बार परीक्षा का नियम राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। फरवरी मार्च में प्रथम मुख्य परीक्षा इसके बाद जून के तीसरे सप्ताह के बाद द्वितीय मुख्य परीक्षा होगी। दूसरी परीक्षा में शामिल होने के लिए पहली परीक्षा के लिए आवेदन करना जरूरी होगा। अब छात्र प्रथम मुख्य परीक्षा में असफल विषयों में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। यह नियम सत्र 2024-25 से पूरी तरह से लागू होगी। बता दें कि सत्र 2023-24 की परीक्षा देने वाले छात्रों को भी दोबारा परीक्षा देने के मौके को लेकर चर्चा भी चल रहा है।

वट सावित्री पर महिलाओं ने की वट वृक्ष की पूजा

रायपुर। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरुवार

को वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की। तपती धूप से बचने के लिए सुबह से ही पति की लंबी आयु को लेकर महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करने के लिए घर से निकल पड़ी थी। शहर तथा मंदिरों में आज महिलाओं की खासी भीड़ सुबह से ही लगी थी। पति के दीर्घायु होने की कामना लेकर महिलाएं निर्जला उपवास कर वट वृक्ष की श्रृंगारमय पूजा करते हुए शहर के अलग-अलग इलाकों में दिखाई दे रही थी। इसी के साथ वट वृक्षों का फेरा लगाते मनोकामना रूपी धागा वट वृक्ष को बांधा, साथ ही वट सावित्री की कथा श्रवण एवं पठन किया।

राष्ट्रीय म्यू थाई चैम्पियनशिप में प्रदेश के चार खिलाड़ियों ने स्वर्ण जीता पदक

रायपुर। राष्ट्रीय म्यू थाई चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस चैम्पियनशिम में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों ने आज राजधानी रायपुर पहुंचकर खेल मंत्री श्री वर्मा से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। खेल मंत्री श्री वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामना दी। उन्होंने प्रतियोगिता में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन कर उनका हौसला बढ़ाया। गौरतलब है कि असम के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टेडियम तेपेसिया, गुवाहाटी में 25 से 30 मई 2024 तक म्यू थाई चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 04 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक एवं 03 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। म्यूथाई खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से मान्यता प्राप्त है तथा पेरिस ओलंपिक-2024 में डेमोंस्ट्रेशन के रुप में शामिल किया गया है। इस राष्ट्रीय चैपियनशिप में 29 राज्यों के लगभग 850 खिलाड़ी और अधिकारियो ने भाग लिया।

सुशासन के लिए होगा आईटी का इस्तेमाल : मुख्यमंत्री साय

पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन के लिए ठोस रणनीति, बजट में 266 करोड़ रुपए का प्रावधान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव की सरकार सुशासन लाने के लिए आईटी का बड़े पैमाने में इस्तेमाल करेगी। जनकल्याणकारी योजनाओं से मॉनिटरिंग से लेकर वित्तीय प्रबंधन करों की वसूली, भूमि संबंधी रिकार्ड के पंजीयन, संधारण और संशोधन सहित सभी जरूरी क्षेत्रों में आईटी का इस्तेमाल होगा। सरकार द्वारा लोगों तक शासकीय योजनाओं की पहुंच का दायरा बढ़ाने के साथ ही प्रशासन को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस पहल करने जा रही है। सरकार के बजट में इन सभी विषयों को शामिल किया गया है। जनकल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अटल डैशबोर्ड की शुरूआत की गई है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर हाल में ही देश के जाने-माने विशेषज्ञों के साथ आईआईएम रायपुर में दो दिनों तक बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सुशासन तथा नागरिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी उपायों का चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में रायपुर-भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों के स्टेट कैपिटल के रूप में विकसित कर विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर तैयार करने का लक्ष्य है। सभी विभागों में आई.टी. के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नवा रायपुर, अटल नगर में लाईवलीहुड सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने का लक्ष्य है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इन्यूबेशन सेंटर की स्थापना तथा बी.पी.ओ. एवं के.पी.ओ. को आकर्षित करने के लिए आई.टी. पार्क की स्थापना की भी योजना है। नवा रायपुर में आई.टी. आधारित रोजगार सृजन हेतु प्लग एण्ड प्ले मॉडल का विकास किया जायेगा, इससे आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के नये अवसर विकसित होंगे।

बजट में छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स की स्थापना सहित प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई.गवर्नेन्स के तहत बजट एण्ड अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किये जाने हेतु (जीआईएस) आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा। शासकीय धन के आय-व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली 2.0 प्रारंभ की जायेगी। पीएम वाणी के अंतर्गत प्रथम चरण में एक हजार ग्राम पंचायतों में वाई.फाई के माध्यम से हॉट-स्पॉट इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। वस्तु एवं सेवाकर के संकलन में सुधार एवं पारदर्शिता के लिए राज्य मुख्यालय में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर संबंधी अपीलीय मामलों के त्वरित निराकरण हेतु अधिकरण की स्थापना की जाएगी।

भूमि एवं भवनों का हस्तांतरण तथा अन्य विविध पंजीकृत संव्यवहार हेतु राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी जिलों में लागू किया जायेगा। भू.नक्शों का जियो.रिफ्रेन्सिंग कराया जायेगा तथा प्रत्येक भू.खंड में यू.एल.पिन नंबर देते हुए भू.आधार कार्ड जारी किया जायेगा। भू.अभिलेखों को सिविल न्यायालयों से लिंक किया जायेगा। भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाईन एवं सरल किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, नए सांसदों को दी बधाई

रायपुर। लोकसभा चुनाव 2024 की बेहतरीन सफलता को लेकर के बीजेपी छत्तीसगढ़ चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए।इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने सभी को जीत की बधाई दी। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की। बैठक में छत्तीसगढ़ के जीते हुए सांसदों को धन्यवाद दिया गया। रायपुर से नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित कई सांसद बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सबसे पहले नए सांसदों का धन्यवाद दिया गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, किरण सिंहदेव सहित बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे।

सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ बड़े नेता दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर सांसदों की मुलाकात होगी इसके बाद पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों में सभी शिरकत करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी लीडर को जिम्मेदारी मिल सकती है इनमें बृजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल का नाम सबसे ऊपर है।

11 को विस अध्यक्ष लेंगे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में समस्याओं को लेकर बैठक

राजनांदगांव। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी और जिला चिकित्सालय की व्याप्त समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य अफसरों की आवश्यक बैठक विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 11 जून को लेंगे।

माना जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था निचले स्तर की हो गई है। चिकित्सकों का नौकरी छोड़ने का क्रम जारी है। स्टॉफ की कमी से मेडिकल कॉलेज में बेहतर चिकित्सा मुहैया कराना मुश्किल हो रहा है जबकि जिला चिकित्सालय की स्थिति भी दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। शहर में दो सरकारी बड़े अस्पताल होने के बावजूद मरीजों को बाहर उपचार कराने के लिए जाना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में सिटी स्केन, एमआरआई की सुविधा नहीं रही है। दोनों अस्पतालों में अच्छे इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों को निजी अस्पतालों के शरण में मजबूरीवश जाना पड़ रहा है।

पिछले एक साल के भीतर 20 से ज्यादा चिकित्सकों ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में कॉलेज की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। कैंसर, मेडिसीन, सर्जरी, आर्थो, ईएनटी समेत अन्य रोगों के विशेषज्ञों ने नौकरी छोड़ दी है। मेडिकल कॉलेज में स्टॉफ नर्स की भी किल्लत है। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की गिरती स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए एक बैठक 11 जून को बुलाई है जिसमें प्रदेश स्वास्थ्य सचिव, राजनांदगांव कलेक्टर, सीएमएचओ समेत अन्य अफसर उपस्थित रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के सांसदों को केंद्रीय मंत्रालय में मिल सकता है मौका!

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा- जितने लोगों को मिले उतना अच्छा है

रायपुर। लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा। प्रदेश की 11 सीटों में से 10 सीटों में भाजपा को जीत मिली है। वहीं मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के सांसदों को केंद्रीय मंत्रालय मिलने की चर्चा तेज हो गई है। यहां से किसे मौका मिलेगा, इस पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जितने लोगों को मिले उतना अच्छा है। प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़े अच्छी बात होगी, कुछ न कुछ अच्छा ही होगा।

छत्तीसगढ़ में भाजपा की बड़ी जीत के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नव निर्वाचित सांसदों और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को गुरुवार को दिल्ली बुलाया है। सीएम साय सभी सांसद गुरुवार को दिल्ली जाएंगे। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। संसदीय दल की बैठक है, उसमें गुरुवार को हम सभी जाएंगे। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस संगठन में बलदाव को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मसला है। लेकिन पीसीसी चीफ दीपक बैज का बस्तर से टिकट काट दिया गया, यह समझने वाली बात है। छग की जनता अनवरत भाजपा के साथ है।

आचार संहिता हटने के बाद सरकार के काम में तेजी आने के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केवल आज का मसला है। शुक्रवार को आचार संहिता हट जाएगी, फिर सभी विभागों में साथ-साथ काम शुरू हो जाएगा। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक पर विजय शर्मा ने कहा कि बैठक में सभी सीटों की समीक्षा होगी। जीत की भी और हार की भी समीक्षा होगी। जहां हार हुई है, तकनीकी तौर पर उन सभी विधानसभा सीटों पर समीक्षा होगी।

2024 के चुनाव में नोटा में पड़े अधिक वोट पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि यह सोचने का विषय है। किसी भी पार्टी का चयन नहीं होना यह सोचने का विषय है।

लोकसभा चुनाव में 8 नए चेहरों को मौका दिया गया था। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, भाजपा में पुराने और नए चहरों का कॉम्बिनेशन है। अगर 8 नए थे तो 33 प्रतिशत पुराने चहरे भी थे।अगर केवल पुराने-पुराने करेंगे तो एंटी इनकंबेंसी होती है।

जाति समीकरण के आधार पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की हुई हार पर विजय शर्मा ने कहा कि जिस सरकार के चेहरे जो लोग थे वह चुनाव में थे। जनता ने उन्हें पहले भी नकारा और अभी भी नकारा है। एक सीट और हमारा आना ही था।

220 में से 198 प्रत्याशियों के जमानत जब्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया। तब से लेकर आज तक राज्य में हुए आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला देखने को मिला है। मतदाताओं ने ज्यादातर अन्य उम्मीदवारों को खारिज कर दिया है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए। नतीजों में भाजपा ने राज्य की 11 सीटों में से 10 सीटें जीतीं है, जबकि कांग्रेस ने एक सीट जीती है।

छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर कुल 220 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के 11-11 प्रत्याशियों को अपनी जमानत बचाने के लिए पर्याप्त वोट मिले, लेकिन शेष 198 उम्मीदवार ऐसा करने में विफल रहे। चुनाव आयोग ने बाकी सभी 198 उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर ली है। लोकसभा चुनाव के इन नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य के मतदाताओं ने अन्य दलों के प्रत्याशियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, किसी उम्मीदवार को अपनी जमानत वापस पाने के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल मतों का कम से कम छठा हिस्सा हासिल करना होता है। यदि कोई उम्मीदवार वैध मतों का आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत हासिल करने में विफल रहता है, तो नामांकन दाखिल करते समय भुगतान की गई उस उम्मीदवार की जमानत राशि चुनाव आयोग जब्त कर लेता है। जमानत राशि सामान्य (ओबीसी सहित) श्रेणी के लिए 25,000 रुपये और अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 12,500 रुपये है।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार श्याम सिंह मरकाम (कोरबा) और एलएस उदय सिंह (सरगुजा) अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन अपनी जमानत बचाने में विफल रहे। जीजीपी ने पिछले साल छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में पाली तानाखार सीट पर जीत हासिल की थी।

बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार इनोसेंट कुजूर (रायगढ़), अश्विनी रजक (बिलासपुर), दिलीप रामटेके (दुर्ग), ममता रानी साहू (रायपुर), डॉ. रोहित डहरिया (जांजगीर-चांपा) और तिलकराम मरकाम (कांकेर) अपनी-अपनी सीट पर तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उनकी भी जमानत जब्त हो गई। इसी तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के फूलसिंह कचलाम बस्तर में चौथे स्थान पर रहे, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई।

छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर तीन चरणों में मतदान कराए गए। 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग हुई। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत कांकेर, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुए। वहीं 7 मई को तीसरे चरण के तहत दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद, सरगुजा और जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुआ था। राज्य में कुल 72.8 प्रतिशत मतदान हुआ था।

गलत जानकारी देकर महतारी वंदन योजना का लाभ ले रहे लोगों की होगी जांच

■ जानकारी गलत निकली तो पैसा मिलना हो जायेगा बंद, वसूली भी होगी

रायपुर। गलत जानकारी देकर यदि महतारी वंदन योजना का लाभ ले रहे हैं तो सतर्क हो जाएं अब विभाग जांच करवा रही है और अपात्र रहे तो बंद हो जायेगा पैसा मिलना। महिला व बाल विकास विभाग ने महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों की पात्रता फिर से जांचने की तैयारी कर ली है। जांच में गलत तरीके से योजना का लाभ लेना पाए जाने पर अपात्र हितग्राहियों से राशि की वसूली भी होगी। विभाग ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाने का निर्णय लिया है जिसमें योजना का लाभ अपात्र महिलाओं के द्वारा लिए जाने की बात सामने आई है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार शासकीय सेवा में पदस्थ, सेवानिवृत्त या पेंशन का लाभ ले रहीं बहुत सी महिलाओं ने आवेदन किया और उनमें से कई महिलाएं योजना से लाभान्वित भी हो रही हैं। ऐसे भी मामले आए हैं, जिनमें एक ही आवेदक ने दो-दो आवेदन किए और दोनों ही स्वीकृत हो गए हैं। ऐसी महिलाओं के खाते में दो-दो बार राशि हस्तांरित हो रही है।

ऐसे अधिकतर मामलों में आवेदकों ने स्वयं के अलावा अपने पति या स्वजन का भी आधार कार्ड नंबर आवेदन में लगाया था। सत्यापन के दौरान यह पकड़ में नहीं आया। विभाग एक नाम वाले 20 हजार से अधिक आवेदनों की जांच कर रहा है। इनमें नाम, पता, जन्मतिथि समान हैं। योजना के लिए 70.26 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 70.14 लाख महिलाओं को पात्र माना गया। 11,771 आवेदन रिजेक्ट हुए थे। पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह एक-एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक चार किस्तों में 2,500 करोड़ से अधिक की राशि जारी हो चुकी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने वालों की जांच कराई जाएगी। अधिकारियों को पारदर्शिता के निर्देश दिए गए हैं। हितग्राहियों के आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

शान्ति सरोवर रिट्रीट सेन्टर में आज से आओ खोलें खुशियों के द्वार-राजयोग अनुभूति शिविर

रायपुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा विधानसभा मार्ग पर स्थित शान्ति सरोवर रिट्रीट सेन्टर रायपुर में 7 से 9 जून तक आओ खोलें खुशियों के द्वार-राजयोग अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर रोजाना दो सत्रों में सुबह और शाम को 7 से 8.30 बजे होगा जिसमें सुविधानुसार किसी भी एक सत्र में भाग लिया जा सकता है। प्रवेश निःशुल्क है। ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार शिविर में भाग लेने वालों के लिए शिविर स्थल पर भी पंजीयन की व्यवस्था की गई है। हैदराबाद की वरिष्ठ एवं अनुभवी राजयोग शिक्षिका ब्रह्माकुमारी राधिका दीदी के सानिध्य में आयोजित इस शिविर मे आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति, कर्मों की गहन गति, भारत के उत्थान और पतन की कहानी, राजयोग अनुभूति और समय की पहचान आदि विषयों पर एक-एक घण्टे का व्याख्यान होगा।

बाहरी चेहरा बना मुद्दा, हार की होनी चाहिए समीक्षा : धनेंद्र साहू

■ छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर कांग्रेस की करारी हार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा एक सीट बढ़ाने में कामयाब रही। उसे इस बार प्रदेश की 11 में से 10 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। वहीं पिछले चुनाव में 2 सीटें जितने वाली कांग्रेस को चुनाव में सिर्फ कोरबा सीट ऐसे जीत मिली है। यहां वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत ने बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय को हराकर यहां से जीत हासिल की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक धनेंद्र साहू ने प्रत्याशियों के गलत चयन को कांग्रेस की इस हार की वजह बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी के बयानों पर पलटवार किया है।

छत्तीसगढ़ में लोकसभा के नतीजों पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा- इस हार की समीक्षा होनी चाहिए। हमारी चुनाव में बड़े चेहरों को लड़ाने पर सहमति बनी थी, लेकिन कोई व्यक्ति बहार

(दूसरी सीटों पर) जाकर चुनाव लड़े इसे लेकर सहमति नहीं थी। बाहरी चेहरे को बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान पर उतारना मुद्दा बना, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। दुर्ग लोकसभा से चार से पांच लोगों को जगह मिली थी, लेकिन हम वहीं से इतनी बुरी तरह से हार गए।

यह हमारी पार्टी का मामला, नेताम को बोलने का कोई हक नहीं

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का लीडर कौन है पता नहीं, पर कांग्रेस की हार का जिम्मा लेने वाला कोई नहीं है। रामविचार नेताम के इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि यह हमारी पार्टी का मामला उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है।

लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि इतनी हड़बड़ी में कोई प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा हो। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है कि उन्हें अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। कहीं कोई बगावत न हो जाए इस डर से वो शपथ की हड़बड़ी कर रहे है।

कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की चुनाव में सफलता को लेकर प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी जीत मिली है। यह खुशी का मौका है। हालांकि, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिणाम निराशाजनक रहे। कभी यहां की सभी सीटें हमारी होती थीं लेकिन अब एक सीट भी नहीं मिली, यह दुख का विषय है।

जातिगत समीकरण के मद्देनजर टिकिट बांटें फिर भी फेल

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट का बंटवारा किया था, लेकिन कई सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। इस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन केवल जाति के लेवल पर किसी को टिकिट नहीं देनी चाहिए। यह भी देखना चाहिए की उस व्यक्ति की समाज में कितनी स्वीकार्यता है, हालांकि, हार के और भी कई कारण होते हैं।

मतदाताओं का अंकुश दिखा इस चुनाव में

नीरजा चौधरी

नतीजे आ चुके हैं और अब सबकी निगाहें आगामी सरकार की संरचना पर टिकी हुई हैं। ये नतीजे मोदी सरकार और भाजपा के लिए एक चेतावनी हैं तथा विपक्ष के लिए यह एक अवसर है। जनता की ओर से यही संदेश आया है कि लोकतंत्र में निरंकुश सत्ता नहीं चल सकती है। यह वोट केवल सरकार के लिए नहीं है, विपक्ष के लिए भी है। लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत विपक्ष की मौजूदगी हो और सरकार ठीक तरह से चले। अगर एक शब्द में निष्कर्ष निकाला जाए, तो मतदाताओं ने अंकुश लगाया है। उन्होंने भाजपा को तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश दिया है, पर उसे नियंत्रित भी किया है। भाजपा नेतृत्व को अब एक गठबंधन सरकार चलाना होगा, सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना होगा तथा अपनी पार्टी के उन नेताओं को लेकर भी सजग रहना होगा, जिन्हें किनारे किया गया है। भाजपा अभी भी विपक्ष की चिंताओं को अनसुना कर सकती है, लेकिन उसे यह अहसास भी रखना होगा कि उसके खाते में साठ से अधिक सीटों की कमी आयी है। लोकतांत्रिक राजनीति में अंकगणित के बदलने के साथ केमिस्ट्री भी बदल जाती है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। लोकसभा के परिणामों के साथ-साथ हमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हुए विधानसभा चुनाव को भी देखना चाहिए। ओडिशा में नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बीजू जनता दल 24 साल से सत्ता में थे। ऐसे में एक थकान थी और पटनायक का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। उन्होंने एक-दो जगह ही सभाएं कीं और प्रचार अभियान से अलग रहे। लोगों को इसका आभास हो गया था और वे चाहते भी नहीं थे कि मुख्यमंत्री प्रचार के लिए निकलें। यह बात भी सामने आयी कि पार्टी और सरकार को पूर्व नौकरशाह वीके पांडियन और कुछ अन्य नौकरशाह चला रहे थे। पांडियन के बारे में यह भी कहा जाने लगा था कि वे आगे चलकर नवीन बाबू के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बन सकते थे। इन कारकों का मिला-जुला असर हमें नतीजों में दिख रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि दूसरी ओर भाजपा के रूप में एक विकल्प तैयार था। भाजपा ने राज्य में बीते पांच वर्षों में बड़ी मेहनत की है, जिसका फायदा उसे मिला है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी सरकार के विरुद्ध एंटी-इनकम्बेंसी थी, जिसके चलते चंद्रबाबू नायडू की वापसी हुई है। नायडू ने खुद भी कहा है कि लोगों ने सत्ता के अहंकार के खिलाफ वोट दिया है। जगन रेड्डी ने नायडू को जेल तक भेज दिया था। चूंकि जगन रेड्डी ने 38 कल्याणकारी योजनाएं चलायी हुई हैं, जिनका व्यापक लाभ लोगों को मिला है, तो माना जा रहा था कि इसके चलते उनकी सरकार बच जायेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा की तरह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के परिणाम भी सत्ता के अहंकार के विरुद्ध आये हैं। भारत का मतदाता आम तौर पर बहुत सहिष्णु होता है और वह अक्सर सरकारों एवं राजनीतिक दलों की गलतियों को अनदेखा कर देता है, लेकिन सत्ता के अहंकार के विरुद्ध प्रतिक्रिया देता है। महाराष्ट्र के नतीजे भी ऐसे ही हैं। वहां पार्टियों में तोड़-फोड़ कर सरकार बनायी गयी। यह रवैया न तो शिव सेना के समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को पसंद आया, न ही एनसीपी के लोगों व मतदाताओं को। राज्य की राजनीति में जो कुछ होता रहा, उससे उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति सहानुभूति पैदा हुई। ये लोग, कांग्रेस भी, एकजुट रहे और अच्छी तरह से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। यहां मैं रेखांकित करना चाहूंगी कि पूरे देश में मुस्लिम समुदाय इंडिया गठबंधन के पीछे पूरी तरह लामबंद रहा। इसका लाभ भी मिला। इस चुनाव में यह भी उल्लेखनीय बात रही कि महिलाओं ने बढ़-चढ़कर मतदान किया। आखिरी दो चरणों में मैंने खुद देखा कि उनकी भागीदारी अधिक थी। ऐसा माना जाता था कि महिलाओं में मोदी के लिए समर्थन ज्यादा रहा है। बिहार में उन्हें नीतीश कुमार का समर्थक माना जाता है। पश्चिम बंगाल में तो वे ममता बनर्जी की राजनीति का मुख्य आधार ही हैं। महिलाओं के लिए कर्नाटक सरकार ने भी अनेक योजनाएं शुरू की हैं और राहुल गांधी एवं इंडिया गठबंधन की ओर से भी महिलाओं को भत्ता देने तथा कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ करने के वादे किये गये।

अब भी मोदी सबसे बड़े नेता हैं

ललित गर्ग

अठाहरवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही अपने अंदर कई संदेशों को समेटे हुए हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, भले ही इंडिया गठबंधन एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ हो, फिर भी तीसरी बार नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए नये भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने के लिये वे पहले दो कार्यकाल से अधिक शक्ति, संकल्प एवं जिजीविषा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीटों के लिहाज से भाजपा को भले ही नुकसान हुआ, लेकिन लगातार तीसरी बार वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ओडिशा और तेलंगाना में पार्टी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। ओडिशा में लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी पार्टी ने बीजू जनता दल का 24 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ा। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 54 प्रतिशत मत और 46 सीटों के प्रचंड बहुमत के बल पर भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई है। वहीं, गुजरात, छतीसगढ़ और मध्य प्रदेश भाजपा के गढ़ बने हुए हैं, जबकि देश की राजनीति में अब भी मोदी सबसे बड़े एवं वर्चस्वी नेता है। वे अब भी अपने चौंकाने वाले एवं आश्चर्य में डालने वाले विलक्षण एवं अनूठे फैसलों से राष्ट्र को विकास की नई उड़ान देते रहेंगे। भाजपा को कम सीटें मिले कारणों की समीक्षा एवं मंथन करते हुए अपनी हार के कारणों को सहजता एवं उदारता से स्वीकारना चाहिए एवं जिन गलतियों के कारण कम सीटें मिली, उन्हें दूर करना चाहिए।

इस बार के चुनाव को नियोजित एवं प्रभावी तरीके से सम्पन्न करने में चुनाव आयोग की भूमिका सराहनीय रही। भले ही इंडिया गठबंधन ने ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाकर देश एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कलंकित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम ने न केवल इस प्रकार के भ्रामक, गुमराह करने वाली बातों एवं मिथकों को तोड़ दिया, बल्कि इसने भारत के जीवंत, बहुलतावादी, पंथनिरपेक्षी और स्वस्थ लोकतांत्रिक छवि को पुनर्स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी का अंधविरोध करने वाला वाम-जिहादी-सम्प्रदायवादी राजनीतिक समूह अपने इस वाहियात प्रलाप एवं राष्ट्र-विरोधी षड्यंत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिये चुनाव परिणाम अनेक अर्थों में संतोषजनक रहे हैं। कांग्रेस के लिये यह चुनाव नये जीवन का वाहक बना हैं। वैसे भी एक आदर्श लोकतंत्र के लिये सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है, यही लोकतंत्र को खूबसूरती देता है। भारतीय मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को विपक्षी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने का संदेश दिया है।

इस बार के चुनाव परिणाम अनेक राजनीतिक दलों के सामने भी अनेक प्रश्न खड़े किये हैं। कौन जेल में रहेगा, इसका फैसला अदालतें करती हैं। परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव को अपने जेल के अंदर रहने या बाहर रहने का अधिकार मतदाताओं को सौंपा था, जिसका नतीजा यह रहा कि उनके शासित वाले दिल्ली में 'आप' का खाता तक नहीं खुला, तो वहीं उनकी पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव-2022 का चमत्कार दोहराने में विफल हो गई और 13 में से केवल 3 सीटें ही जीत पाई। शरद पवार का राजनीतिक वारिस कौन और असली शिवसेना किसकी? क्या माया और ममता अब भी ताकतवर हैं? यह चुनाव ऐसे ही कई सवालों के साथ शुरू हुआ था। इनमें से कुछ के जवाब मिल गए हैं और कुछ के बाकी हैं। जिस तरह के नतीजे आए हैं, उससे यह संदेह भी पैदा हुआ है कि क्या देश में आर्थिक सुधार जारी रहेंगे? क्या देश विकास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा? नीतिगत स्थिरता का क्या होगा? शायद इसी संदेह की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। लेकिन नरेन्द्र मोदी के पहले भाजपा मुख्यालय में दिये उद्बोधन एवं गठबंधन दलों के साथ हुई बैठक में इन सवालों के जवाब काफी हद तक मिल गये, जिससे शेयर बाजार ने भी तेजी पकड़ी है एवं भाजपा एवं सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है।

देश एक बार फिर गठबंधन सरकारों के युग में प्रवेश कर रहा है। अब यह एक हकीकत है कि मौजूदा जनादेश के मद्देनजर गठबंधन सरकार बनाना भाजपा की मजबूरी हो गई है। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाने और अल्पमत में सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाने में बड़ा फर्क है। सवाल उठाया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत वाले दो कार्यकालों में देशहित के बड़े फैसले लेने वाली भाजपा क्या गठबंधन के सहयोगियों के दबाव के बीच शासन करने में खुद को सहज महसूस कर सकेगी? लेकिन मोदी के नेतृत्व में सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और अपने संकल्पों एवं योजनाओं को आकार देगी, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आती। देश में केंद्रीय स्तर 2009 के बाद पहली बार गठबंधन सरकार बनने जा रही है। अतीत में नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सरकारों का कुशलता से संचालन भी किया है और आवश्यक सुधारों को भी आगे बढ़ाया है। मनमोहन सिंह ने भी दस वर्ष तक गठबंधन सरकार का संचालन किया है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उन्हें किस तरह कई बार सहयोगी दलों के अनुचित दबाव में झुकना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी भी गठबंधन सरकार की चुनौतियों से जूझते रहे। लेकिन मोदी की स्थितियां भिन्न है, वे राजनीति के धुंरधर खिलाड़ी है, अमित शाह राजनीतिक जोड़ तोड़ के खिलाड़ी है, इसे देखते हुए भाजपा और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक अपना काम कर सकेगी, ऐसा विश्वास है। न केवल सरकार बल्कि भाजपा के बड़े मुद्दों का भी क्रियान्वयन होगा। जब-जब भाजपा के सामने अनुचित राजनीतिक दबाव की स्थितियां बनेगी, सरकार कोई सार्थक रास्ता निकाल लेगी।

वैसे भी भाजपा बहुमत के आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि तेलुगु देसम पार्टी, जनता दल-यू, शिवसेना समेत अन्य सहयोगी दलों के साथ उसके लिए सरकार चलाना कहीं अधिक आसान होगा। इसके बाद भी इतना तो है ही कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गठबंधन सरकार का संचालन करेंगे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के तहत कार्य करने के कारण वह ऐसी सरकार के संचालन के तौर-तरीकों से अवगत हैं, लेकिन स्वयं उनके लिए ऐसी सरकार चलाना एक नया अनुभव होगा। लेकिन वे भाजपा संगठन में अनेक पदों पर रहते हुए संगठन की गतिविधियों के कुशल संचालन से भिज्ञ है। देश-विदेश के दबावों को झेलते हुए उन्होंने भारत को एक शक्ति के रूप में खड़ा किया है, दुनिया जब आर्थिक संकट झेल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, निश्चित ही गठबंधन सरकार का उनका संचालन उनकी नेतृत्व क्षमता और सबको साथ लेकर चलने के राजनीतिक कौशल को एक नया आयाम देगी। उनके पास चुनौतियों के बीच देश की समस्याओं का समाधान करने की एक राजनीतिक दृष्टि एवं कौशल है।

गठबंधन सरकारों के कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी। गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले को घटक दलों से समन्वय के साथ चलना होता है। इसमें समस्या तब आती है, जब घटक दल अनुचित मांगें मनवाने लगते हैं अथवा सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए दबाव की राजनीति करने लगते हैं। इन स्थितियों की निबटने के लिये मोदी सरकार पहले ही अन्य निर्दलयी सांसदों एवं अन्य राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ने का उपक्रम कर रही है। सहयोगी दल अनुचित मांग एवं दबाव की बजाय अपने राज्य के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की चिंता करें, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें राष्ट्रीय हितों को ओझल नहीं करना चाहिए। यह उन्हें भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गठबंधन सरकार सुगम तरीके से चले।

निश्चित ही मोदी सरकार के सामने चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, जिस तरह महाभारत युद्ध में पांडवों के सामने जटिल स्थितियां थी। आज द्रोण नहीं तुष्टिकरण है, कृपाचार्य नहीं भ्रष्टाचार है, अश्वत्थामा नहीं आतंकवाद है, दुर्योधन नहीं महत्वाकांक्षा एवं अनैतिकता है, शकुनि नहीं आंतरिक और वैश्विक षड्यंत्र है, राष्ट्रवाद नहीं समस्त प्रकार की विघटनकारी शक्तियां-भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, स्वार्थवाद आदि हैं और कर्ण नहीं कट्टरवाद है। साथ में महंगाई, बेरोजगारी, असंतोष आदि की अत्यंत जटिल समस्याएं भी हैं और अब भारत इनमें फंसा हुआ है। फिर भी नरेन्द्र मोदी रूपी उजाला अपनी नई पारी में अधिक सशक्त होकर भारत के इन सभी चक्रव्यूह को भेदेगा। अपने राजनीतिक जीवन की सबसे सफलतम पारी खेलते हुए वह एक बार फिर नकारात्मक एवं अराष्ट्रवादी शक्तियों को उनकी जमीन दिखायेंगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

सुबालोपनिषद् (भाग-4)

गतांक से आगे...

यह पृथिवी जल में लय हो जाती है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश इन्द्रियों में, इन्द्रियाँ तन्मात्राओं में, तन्मात्राएँ भूतादि (अहंकार) में, अहंकार-महत् तत्त्व में, महत् तत्त्व अव्यक्त में, अव्यक्त अक्षर में, अक्षर तमस् (अज्ञान) में लय हो जाता है और तमस् परम देव (परमेश्वर) में एकाकार हो जाता है। इसके पश्चात् न संत् रहता है, न असत् रहता है और न सत्-असत् का सम्मिलित रूप रहता है। यही निर्वाण का अनुशासन है और यही वेद का अनुशासन एवं शिक्षा है।

द्वितीय खण्ड में विश्वोत्पत्ति के पूर्व की स्थिति सत-असत् से परे कही गई है। यहाँ दूसरा मत प्रकट करते हुए ऋषि कहते हैं- प्रथम सृष्टि के पूर्व यह जगत् असत् (अस्तित्व में होते हुए भी अप्रकट या अव्यक्त) था। यह आत्मा उससे उत्पन्न नहीं हुई है और न ही उसने इससे प्रतिष्ठा पायी है। वह आत्मा अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस, अगन्ध, अव्यय है, न महान् है, न विस्तार युक्त है, वह जन्म रहित (अजन्मा) है, ऐसा मानकर धीर पुरुष शोक नहीं करते।

यह आत्मा प्राण रहित, मुख रहित, श्रोत्र रहित, वाणी रहित, मन रहित, तेज रहित, नेत्र रहित, अनाम, अगोत्र, सिर रहित, बिना हाथ-पैर का, स्नेह रहित, अलोहित (रक्तरहित अथवा रज आदि गुणत्रय रहित) और अप्रमेय है। यह न लम्बा है, न मोटा है, न स्थूल है, न छोटा है, न कम है। यह अपार है, इसे बताया भी नहीं जा सकता। यह अनावृत है, इसके नियम पर तर्क नहीं किया जा सकता, यह अप्रकाश्य है, असंवृत (असंकीर्ण) है, अन्तर-बाह्य रहित है, न वह कुछ खाता है और न कोई उसे खाता है। इसे सत्य, दान, अनशन प्रधान तप, ब्रह्मचर्य, अखण्ड वैराग्य और अनाशक (स्त्री आदि विषय भोगों के प्रति आसक्ति रहित होना) इन षट् साधनों द्वारा ही जानना चाहिए।

क्रमशः ...

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

रमेश सर्राफ धमोरा

भोजन की कमी व दूषित भोजन खाने से प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतृत्व करने और पौष्टिक खाने के प्रति लोगों को जागरुक करने की जिम्मेदारी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में पहली बार खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया था। इसके बाद पहली बार 7 जून 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। तब से हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाने लगा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इससे खाद्य सुरक्षा लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है और विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियों को भी ध्यान में लाया जा सकता है। इस दिन को मनाने के पीछे खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगो को जागरूक करने का उद्देश्य था। जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों के शिकार बन जाते हैं।

रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती है। जिसके बिना मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल है। इसमें रोटी सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि रोटी के बिना तो मनुष्य जिन्दा भी नहीं रह सकता है। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर दस में से एक व्यक्ति दूषित भोजन का सेवन करने से बीमार पड़ जाता है। जो कि सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है।

भारत में हर वर्ष जितना भोजन तैयार होता है उसका एक तिहाई बर्बाद चला जाता है। बर्बाद जाने वाला भोजन इतना होता है कि उससे करोड़ो लोगों की खाने की जरूरत पूरी हो सकती है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में बढ़ती सम्पन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विश्व खाद्य संगठन के अनुसार देश में हर साल पचास हजार करोड़ रूपये का भोजन बर्बाद चला जाता है। एक ऑकलन के मुताबिक बर्बाद होने वाले भोजन की धनराशि से पांच करोड़ बच्चों की जिदगी संवारीं जा सकती है।

इस संदर्भ में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य अपव्यय को रोके बिना खाद्य सुरक्षा सम्भव नहीं है। इस रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य अपव्यय का अध्ययन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करते हुए बताया है कि भोजन के अपव्यय से जल,जमीन और जलवायु के साथ साथ जैव-विविधता पर भी बेहद नकारात्मक असर पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारी लापरवाही के कारण पैदा किए जाने वाले अनाज का एक तिहाई हिस्सा बर्बाद कर दिया जाता है। देश में एक तरफ करोड़ो लोग खाने को मोहताज है। वहीं लाखों टन खाना प्रतिदिन बर्बाद किया जा रहा है।

मोदी ब्रांड की छवि पर आघात से दुनिया भी हैरान है

नीरज कुमार दुबे

भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दशक काफी बड़े और कड़े फैसलों वाला रहा और उनके निर्णयों और नेतृत्व की धमक देश में ही नहीं पूरी दुनिया में रही जिसके चलते वह समूचे विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में उभरे। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम उनके लिए आश्चर्य लेकर आये जब उनकी पार्टी भाजपा ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया और सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों पर निर्भर हो गयी। इन चुनाव परिणामों ने मोदी की अजेय रहने वाले नेता की छवि पर बहुत बड़ा असर डाला है जिसकी गूंज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है। देखा जाये तो भारत में तो विपक्ष मोदी को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुँचाना चाहता ही था साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसी शक्तियां थीं जोकि मोदी की ग्लोबल लीडर के रूप में पुख्ता होती छवि को नुकसान पहुँचाना चाहती थीं। कह सकते हैं कि भारत में विपक्ष को और विदेशों में भारत विरोधी शक्तियों को कहीं ना कहीं अपने मिशन में थोड़ी-बहुत कामयाबी मिल गयी है। लेकिन यह भी सत्य और एक तथ्य है कि मोदी की कार्यशैली मक्खन पर नहीं अपितु पत्थर पर लकीर खींचने की है इसलिए वह तीसरे कार्यकाल में अपने कामकाज से विरोधियों को तगड़ा जवाब अवश्य ही देंगे।

चुनाव परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि अबकी बार 400 पार के नारे की ही नहीं बल्कि मोदी है तो मुमकिन है और जो राम को लाये हैं हम उनको लाएंगे जैसे नारों की भी हवा पूरी तरह निकल गयी है। चुनाव प्रचार की बात हो या भाजपा के संकल्प पत्र में किये गये वादों की, सब कुछ मोदी की गारंटी के ही इर्दगिर्द केंद्रित था इसलिए कहा जा सकता है कि मोदी ब्रांड की छवि पर सीधा असर पड़ा है।

इसलिए अब समय आ गया है जब भाजपा को सिर्फ मोदी नाम के सहारे रहने की बजाय और भी पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। जबसे मोदी केंद्र की राजनीति में आये हैं तबसे यही देखने को मिलता है कि पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव पर भाजपा सिर्फ मोदी नाम के सहारे ही रहती है। भाजपा ने चुनाव में मोदी की गारंटी के अलावा %वकास भी और विरासत भी का नारा दिया था और करोड़ों लोगों के गरीबी रेखा से बाहर निकलने तथा भारत के सांस्कृतिक गौरव की बहाली की दिशा में उठाये गये कदमों का हवाला दिया था फिर भी वह स्पष्ट बहुमत से बहुत दूर रह गयी।

दूसरी ओर, भाजपा की सीट घटने से सिर्फ पार्टी के ही नेता हैरान और परेशान नहीं हैं बल्कि कई विदेशी नेता भी इस बात से हैरान हैं कि दिन-रात अपने देश के लिए काम करते रहने वाले प्रधानमंत्री को चुनावों में जनता ने क्यों सजा दे दी है। आप दुनिया भर की समाचार वेबसाइटों को देखेंगे तो सभी ने मोदी की सीटें घटने पर हैरानी जताई है। इन चुनाव परिणामों ने मोदी के विदेशों में रुतबे को निश्चित रूप से प्रभावित किया है। दरअसल, जिस तरह का माहौल बनाया गया था उसमें ना तो देश में और ना ही दुनिया में किसी को इस तरह के चुनाव परिणामों की अपेक्षा थी। यही कारण है कि भाजपा तो अपने चुनावी प्रदर्शन पर मंथन कर ही रही है दुनिया के भी कई बड़े नेता भारत के चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसके कारणों की समीक्षा कर रहे हैं।

हम आपको यह भी बता दें कि साल 2024 में दुनिया के अधिकांश देशों में चुनाव होने हैं। कई छोटे-बड़े देशों में जून महीने की शुरुआत तक चुनाव हो चुके हैं और अमेरिका सहित कई अन्य देशों में चुनाव इस साल के अंत से पहले होने हैं। एक खास बात यह है कि अब तक जितने देशों में चुनाव हुए हैं उनमें से ज्यादातर में सरकारें वापस सत्ता में नहीं लौटी हैं लेकिन मोदी दस साल राज करने के बाद भी तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौट आये हैं। भले उनकी सीटों की संख्या कम हो गयी है लेकिन काम करने के लिए उनके पास स्पष्ट जनादेश है। मोदी ने जब 2014 में भारत सरकार की कमान संभाली थी तबसे दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष बदल चुके हैं लेकिन मोदी सत्ता में कायम हैं जिसका सीधा मतलब यही है कि जनता को उनके नेतृत्व और उनकी नीतियों में विश्वास है। यह विश्वास ही तो है कि विपक्ष के घोषणापत्र में की गयी फ्री की तमाम सौगातों की बजाय जनता ने मोदी के वादों को तवज्जो दी है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक की बात करें तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हार-जीत राजनीति का हिस्सा है और नंबरगेम चलता रहता है। उन्होंने कहा है कि लेकिन इस सबका असर देश के विकास पर नहीं पड़ना चाहिए। वैसे देखा जाये तो लोकतंत्र में नंबरगेम ही मायने रखता है लेकिन मोदी के लिए इसका खास महत्व नहीं है। इस बात को हम गुजरात के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा ने 2002 में 127 सीटों पर जीत हासिल की थी उसके बाद पार्टी अगले चुनाव में 117 सीटों पर और उसके बाद 116 सीटों पर पहुँच गयी थी। यही नहीं, मोदी के दिल्ली आने के बाद गुजरात में जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भाजपा 99 सीटों पर आ गयी थी लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने गुजरात में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये थे। नंबरगेम ऊपर नीचे होता रहा लेकिन मोदी ने गुजरात के विकास को जरा भी प्रभावित नहीं होने दिया।

बहरहाल, देखा जाये तो लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले तक माना जाता था कि देश में मोदी के बराबर का कोई नेता नहीं है लेकिन विपक्ष के तमाम नेताओं को जनता ने जो ताकत दी है उससे मोदी के आसपास अब कई नेता खड़े हो गये हैं। नई संसद में जो दलीय स्थिति बनी है और स्पष्ट बहुमत की बजाय गठबंधन सरकार की जो नौबत आई है उसको देखते हुए मोदी की चुनौतियां तो बढ़ गयी हैं लेकिन मोदी चुनौतियों को चुनौती देकर मंजिल पर समय से पहले पहुँचने वाले नेता हैं यह बात सबको याद रखनी चाहिए।

आज का इतिहास

1944 ब्रैविल की लड़ाई शुरू हुई।
1948 वामपंथियों ने पूरी तरह से चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया।
1949 डॉक वर्कर्स ने यूनाइटेड किंगडम में हड़ताल शुरू की।
1954 प्रारंभिक कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने आत्महत्या की।
1965 अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ग्रिसवॉल्ड बनाम कनेक्टिकट में फैसला सुनाया कि कॉन्टीकटिक कानून जिसमें गर्भ निरोधकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था, ने %वैवाहिक गोपनीयता के अधिकार% का उल्लंघन किया था।
1967 इज़राइली सैनिक छह दिनों के युद्ध के दौरान यरूशलेम शहर में प्रवेश कर गए। यह युद्ध 3 अरब देशों और इजरायल के बीच लड़ा गया था। अरब देशों में शामिल हैं- जॉर्डन, मिस्र और सीरिया। पूर्वी यरुशलम पर इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिण नदी तट के साथ कब्जा कर लिया था।
1975 पहला क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में शुरू हुआ। यह 14 दिनों तक चलने वाला टूर्नामेंट था जिसमें 8 क्रिकेट देशों ने हिस्सा लिया था। 60 ओवर की पारी टीमों ने खेली। वेस्टइंडीज 1 विश्व कप का चैंपियन बना।
1975 उद्घाटन क्रिकेट विश्व कप, पुरुषों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल, इंग्लैंड में शुरू हुआ।
1981 इज़राइली वायु सेना ने ओसिरक न्यूक्लियर ट्रेक्टर पर हमला किया और उसे निष्क्रिय कर दिया, यह मानते हुए कि इराकी परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्लूटोनियम का उत्पादन कर रहा था।
1982 टेनेसी, मेम्फिस, टेनेसी में एल्विस प्रेस्ली की हवेली, प्रेस्ली के जीवन के संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खोला गया।
1995 बोइंग 777 ने अमेरिकी एयरलाइंस में अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू की। बोइंग 777 दुनिया का सबसे बड़ा ट्विनजेट एयरो विमान है। यह एक लंबी दूरी का एक बड़ा विमान है। इसका परिचालन दायरा लगभग 20000 किमी है।
1998 तीन श्वेत वर्चस्ववादियों ने अफ्रीकी अमेरिकी जेम्स बर्ड, जूनियर की हत्या कर दी, एक पिक-अप ट्रक के पीछे उसका पीछा करते हुए और उसे टेक्सास के जैस्पर में नासापट रोड पर खींचकर ले गए।
2001 टोनी ब्लेयर की लेबर पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल किया।

पहेली बना आरएसएस-भाजपा का संबंध

हरीश गुप्ता

2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा 543 सदस्यों वाली लोकसभा में 272 सीटों के जादुई आंकड़े से चूक गई, जिससे मोदी के लाखों प्रशंसकों को झटका लगा होगा। लेकिन संघ परिवार के कई लोगों का मानना है कि इस तरह की परिस्थिति के लिए भाजपा नेतृत्व ही जिम्मेदार है। उनका कहना है कि भाजपा ने आरएसएस नेताओं द्वारा दी गई शुरुआती चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने भाजपा को ग्रामीण इलाकों में किसानों के संकट और अन्य कमजोरियों से अवगत कराया था और आग्रह किया था कि बिना देरी किए इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन भाजपा अति-आत्मविश्वास में थी और अपनी ही दुनिया में जी रही थी। आरएसएस 2004 के उस पल को दोहराता जाता देख रहा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी 'इंडिया शाइनिंग' की लहर पर सवार थे और मुट्ठी भर लोकसभा सीटों से चूक गए थे।

2024 में, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 20 साल बाद वही किया और आसमान छूते शेयर बाजार पर भरोसा किया। उसने 'अबकी बार ।।। 400 पार' करके इतिहास रचने का दावा किया। अति उत्साह में भाजपा ने राज्यों में पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की परवाह नहीं की और उनमें से कुछ को अपमानित भी किया गया। लोकसभा के टिकट पुरानी परंपरा के अनुसार अन्य हितधारकों की सिफारिशों को नजरअंदाज कर मनमाने ढंग से बांटे गए। यहां तक कि जिला स्तर पर भाजपा में प्रतिनियुक्त आरएसएस प्रचारकों की राय लेने की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। इसी पृष्ठभूमि में एक रिपोर्ट सामने आई कि आरएसएस और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 19 अप्रैल को नागपुर में जब प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम कर रहे थे, उस समय

जो कुछ हुआ, उस पर कोई भी टिप्पणी करने को तैयार नहीं था।

दागी नेताओं के लिए खुले दरवाजे की नीति और पार्टी के वफादारों की अनदेखी की भाजपा की आक्रामक रणनीति से आरएसएस नेतृत्व चिंतित था। प्रचंड बहुमत हासिल करने के लिए भाजपा की अलग हटकर बनी छवि से समझौता किया गया। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपना वोट डालने के लिए शहर में ही थे, लेकिन इस मुद्दे पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। इन सबके बीच एक और बात तब सामने आई जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के बीच एक इंटरव्यू में कहा कि पार्टी को शुरुआती दौर में आरएसएस की जरूरत थी। उन्होंने कहा, 'अब जब पार्टी बड़ी और सक्षम हो गई है, तो भाजपा अपने दम पर चल सकती है।' यह आरएसएस को साफ संदेश था कि भाजपा को अपने राजनीतिक कामों में मदद करने के लिए अब उसके प्रचारकों की जरूरत नहीं है।

पिछले कुछ महीनों से भाजपा महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष का मीडिया की नजरों से गायब रहना काफी हद तक इसी वजह से हो सकता है। संघ परिवार के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मौजूदा भाजपा सरकार को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पीछे से किसी की भूमिका पसंद नहीं आई। आरएसएस इसका वैचारिक मार्गदर्शक बना रहेगा, लेकिन इसकी रोजमर्रा की गतिविधियों में इसकी कोई भूमिका नहीं होगी। कहा जाता है कि इन चुनावों में भी आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। 1952 में जब से आरएसएस ने भारतीय जनसंघ के नाम से अपनी राजनीतिक शाखा शुरू की है, तब से यह पहली बार है जब उसने उम्मीदवारों के चयन और संबंधित गतिविधियों सहित चुनाव प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाई है। लोकसभा चुनावों में भाजपा को बड़ा झटका मिलने के बाद, उनके भविष्य के रिश्ते पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 45 दिनों तक चलने वाले अब तक के सबसे लंबे लोकसभा चुनाव कराने में अपनी गलती स्वीकार कर ली है। देश के संसदीय इतिहास में दूसरी बार हुआ कि आधुनिकतम तकनीक होने के बावजूद यह अत्यधिक लंबा चुनाव था। भारत को 1947 में जब स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद 1952 में पहला आम चुनाव 25 अक्तूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। लेकिन राजीव कुमार यह बताने में विफल रहे कि उन्होंने भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी 'रेड अलर्ट' की अनदेखी क्यों की, जिसमें कहा गया था कि मई के मध्य से उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ेगी। वे लोकसभा चुनाव एक महीने पहले करा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके कारण अप्रैल-मई के दौरान चुनाव आयोग की ड्यूटी पर तैनात लोगों की मौत हो गई। भले ही उन्हें समझ में आ गया हो, लेकिन नुकसान हो चुका है।

18 वीं लोकसभा के नतीजों ने लगभग सभी को खुश होने का मौका दे दिया है। भाजपा खुश है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस जीत का श्रेय पार्टी और एनडीए को दे रहे हैं। पार्टी के पुराने वफादार नेता खुश हैं क्योंकि अब उनकी आवाज सुनी जा सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी मुस्कुराने का मौका है क्योंकि 2019 के मुकाबले भाजपा ने जो 29 लोकसभा सीटें खो दी हैं, उसमें उम्मीदवारों के चयन में उनकी कोई अहम भूमिका नहीं थी।

कांग्रेस खुश है कि उसने वापसी की और राहुल गांधी ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। भाजपा के सहयोगी खुश हैं कि भाजपा अब 'गठबंधन धर्म' का पालन कर सकती है। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद विपक्षी नेताओं को 'ईश्वरीय न्याय' मिलने की उम्मीद है। पंजाब में अकाली दल जैसी कई क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा ने किनारे कर दिया था, लेकिन उनके पास मुस्कुराने का मौका है क्योंकि भगवा पार्टी वहां एक भी सीट नहीं जीत पाई। हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में जेजेपी के लिए भी यही बात लागू होती है। महाराष्ट्र में भी सभी के पास मुस्कुराने का मौका है। आखिरकार ईवीएम ने सभी आरोपों को खत्म करते हुए लंबी लड़ाई जीत ली है।

लोकतांत्रिक संतुलन बनाते चुनाव परिणाम

राजेश बादल

भारत ने नया जनादेश दे दिया है। परिणामों ने एग्जिट पोल के रुझानों को झटका दिया है। इस चुनाव का जनादेश एक नजरिये से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करता दिखाई दे रहा है। भले ही एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन परिणामों ने प्रतिपक्ष के लिए संजीवनी का काम किया है। यह संजीवनी प्रजातंत्र के लिए भी है क्योंकि बिना असहमत पक्ष के लोकतंत्र नहीं चलता। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस मुल्क के मतदाताओं ने जिस शिखर बिंदु पर पहुंचाया था, उसने पार्टी में अहंकार और अधिनायकवादी बीजों को अंकुरित कर दिया था। इन बीजों का असर 2024 के इस चुनाव में भी दिखाई पड़ा। इसी वजह से यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने के नाम पर लड़ा गया। प्रतिपक्ष दरअसल पिछले चुनाव में अत्यंत दीनहीन, दुर्बल और महीन आकार का था। इसलिए उससे नीचे, उसके जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था और भारतीय जनता पार्टी जहां पर थी, उससे ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं थी। जब एनडीए के नेता अपने प्रचार अभियान में तीन सौ और चार सौ पार का नारा लगा रहे थे तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन अपनी एकता को साबित करने की कोशिशों में जुटा था। एनडीए का अभियान प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही केंद्रित रहा। भाजपा कार्यकर्ता अति विश्वास में थे। यही विश्वास उन्हें झटका दे गया। भाजपा को बड़ा सदमा उत्तर प्रदेश से लगा। इस विराट महाप्रदेश ने अधिकांश मुद्दों की हवा निकाल दी। न तो राममंदिर निर्माण का जादू चला और न सांप्रदायिक विभाजन काम आया। परिणामों का संकेत यही है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन का नारा भी काम नहीं आया। पार्टी बेरोजगारी,भ्रष्टाचार और महंगाई जैसी समस्याओं से निपटने में नाकाम रही। बसपा के मतदाता वर्ग का छिटकना भी इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद रहा। बहुजन समाज पार्टी का कट्टर वोट बैंक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर स्थानांतरित हो गया। यह पार्टी के लिए बड़ा सबक है। रही-सही कसर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयानों ने पूरी कर दी। बिहार में उन्होंने साफ कहा कि छोटे और क्षेत्रीय दलों का कोई भविष्य नहीं है। इससे एनडीए में शामिल छोटे दल उससे दूर होते चले गए। नड्डा ने दूसरा बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नाराज करने वाला दिया। उन्होंने कहा कि अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है। इससे संघ भी खफा हो गया। वैसे तीसरी बार सरकार एनडीए की बनने में कोई बाधा नहीं नजर आती। भारत के चुनाव इतिहास में यह पहला अवसर होगा, जबकि कोई गैरकांग्रेसी सरकार लगातार तीसरी बार काम संभालेगी। कांग्रेस की ओर से सिर्फ जवाहरलाल नेहरू यह करिश्मा कर सके हैं। लेकिन 1952 के आम चुनाव का परिदृश्य कुछ और था, जबकि 2024 के भारत की तस्वीर एकदम भिन्न है। वह सदियों की गुलामी से मुक्ति पाया अनगढ़ हिंदुस्तान था। उसे पेशेवर शिल्पी की तरह रचने और लोकतांत्रिक आकार में तराशने का बेहद कठिन काम जवाहरलाल नेहरू ने किया और उन्होंने जो नींव तैयार की, उस पर इमारत खड़ी करने का काम बाद के प्रधानमंत्रियों ने किया। इस कड़ी में जम्हूरियत को और पुख्ता करने का काम भाजपा सरकार और उसके नेता नरेंद्र मोदी पर आन पड़ा है। हम उम्मीद करें कि बहत्तर साल पुराना संसदीय प्रजातंत्र भविष्य में और अधिक चमकीला तथा भरोसेमंद साबित होगा।

चुनाव में जो जीता, वही सिकंदर

राजकुमार सिंह

यह आपके नजरिये पर निर्भर करता है कि गिलास को आधा भरा देखते हैं या आधा खाली। अठारहवीं लोकसभा के चुनाव परिणाम को इसी नजरिये से देखा जा सकता है। चार जून की मतगणना का यह नतीजा तो साफ है कि 400 पार का नारा देनेवाला राजग 300 तक पहुंचते-पहुंचते हांफ गया, पर केंद्रीय सत्ता की 'हैट्रिक' अपने आप में कम बड़ी उपलब्धि होगी क्या? पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के बाद वह करिश्मा कर पानेवाले नरेंद्र मोदी देश में दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। तीन दशक के अंतराल के बाद, 2014 में किसी एक दल के रूप में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिलाने का श्रेय भी मोदी को गया. मोदी काल में ही भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी और देश के ज्यादातर राज्यों में सत्तारूढ़ भी हुई। भाजपा की उस छलांग और फिर इस चुनाव में अपने लिए 370 के लक्ष्य को ध्यान में रखें तो चुनाव परिणाम निश्चय ही निराशाजनक लगते हैं। 370 का नारा देनेवाली भाजपा अगर बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में ही हांफ गई तो जाहिर है कि आत्मविश्लेषण की जरूरत होगी। बेशक वह आत्मविश्लेषण होगा भी, लेकिन क्या भाजपा को ऐसे उलटफेर की तनिक भी आशंका नहीं थी? जाहिर है, कोई भी राजनीतिक दल ऐसी स्वीकारोक्ति का साहस नहीं दिखाता, पर प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपाई रणनीतिकारों की कवायद पर नजर डालें तो समझना मुश्किल नहीं कि उन्हें इसकी आशंका थी- और उन्होंने संभावित नुकसान की भरपाई की हरसंभव कोशिश भी की। पिछले साल विपक्षी दलों का गठबंधन 'इंडिया' बनने के पहले से ही भाजपाई रणनीतिकार सक्रिय हो गए थे। महाराष्ट्र में जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ, उसका उद्देश्य सिर्फ वहां की सत्ता तक सीमित नहीं था। भाजपा को अहसास था कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र में मुश्किलें पेश कर सकता है। इसीलिए शिवसेना और राकांपा में क्रमश: एकनाथ शिंदे और अजित पवार के जरिये विभाजन करवाया गया। उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर करने का तात्कालिक लक्ष्य तो भाजपा को हासिल हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम के झटके से वह नहीं बच पाई। जिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मानसिक स्वास्थ्य पर संदेह समेत तमाम तरह के हमले भाजपा करती रही, उन्हें भी एक बार फिर अपने पाले में इसीलिए लाया गया कि 'इंडिया' रफ्तार पकड़ने लगा था। अपना चुनावी गणित बेहतर करने के लिए ही भाजपा उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल को राजग के पाले में लाई, जो पिछले एक दशक से सपा से गठबंधन में राजनीति कर रहा था। लेकिन विश्वसनीय स्थानीय नेतृत्व तथा क्षेत्रीय जनमानस को समझे-स्वीकारे बिना चुनावी रण नहीं जीता जा सकता- चुनाव परिणामों का यह संदेश सभी दलों के लिए एक जरूरी सबक है।

सपा की सटीक फॉर्मूले से भाजपा पस्त

राजीव सिंह

यूपी विधानसभा 2007 के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मायावती ने पहली बार सबसे सफल तरीके से अपनाया था। दलितों के साथ सवर्ण को जोड़कर उन्होंने अपने दम पर विधानसभा चुनाव जीत लिया था। इसी सोशल इंजीनियरिंग पर मुलायम सिंह यादव ने बदलाव कर यादव, मुस्लिम और कुछ सवर्ण को जोड़कर 2012 में जीत हासिल कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। इधर, इसके बाद राम मंदिर मुद्दे के प्रभावी ढंग से आगे आने से सोशल इंजीनियरिंग का प्रभाव 2017 और 2022 के चुनाव में कम जरूर हुआ लेकिन भाजपा सहित हर पार्टी इस समीकरण को टिकट वितरण में जरूर ध्यान रखती थी। चूंकि राम मंदिर मुद्दा भी हावी था और 2022 में राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था, सुरक्षा, मुफ्त अनाज, किसानों को नकद लाभ भी बड़ा मुद्दा बना इसलिए इन दोनों चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग जैसा तरीका कमजोर पड़ गया था। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव, कांग्रेस के साथ मिलकर सोशल इंजीनियरिंग के ज्यादा बेहतर और असरकारक फॉर्मूले को अपना कर सफल साबित हुए।

दरअसल, चुनाव से चंद दिनों पूर्व ही सामने आए उनके पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले ने पूरा चुनाव नतीजों को ही पलटकर रख दिया और भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। सपा की यह रणनीति इतनी कारगर साबित हुई है कि राज्य के हर क्षेत्र चाहे वह पश्चिम हो, मध्य हो या पूर्वांचल सब जगह भाजपा बुरी तरह पस्त हुई है। पूर्वांचल जहां नरेंद्र मोदी स्वयं चुनाव मैदान में थे भाजपा का एक तरह से सफाया जैसा हो गया है। मतदान का यही पैटर्न बना रहा तो अगले विधानसभा

चुनाव भाजपा के लिए बड़े खतरे की घंटी है, और यह एक ऐसा खतरा होगा जिसके आगे राम मंदिर, राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था, विकास, मुफ्त अनाज और सुशासन जैसे मुद्दे बेहद गौण साबित हो सकते हैं। देश के सबसे बड़े इस राज्य की सत्ता को बचाए रखना बीजेपी के लिए जीवन-मरण का सवाल होगा और इसके लिए अभी से बेहद मजबूत रणनीति और आम आदमी को राहत पहुंचाने वाले मुद्दों के साथ तैयारी करनी होगी। दरअसल, यह ध्यान रखना चाहिए कि भले ही यूपी के नतीजे चौंकाने वाले लग रहे हो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे सपा और कांग्रेस की एक सोची-समझी एक रणनीति ने भी काम किया है। वैसे भी चुनाव एक प्रयोगशाला की तरह ही होते है और आपके नपे-तुले और सटीक फॉर्मूले ही आपको जीत दिला सकते हैं। भाजपा के लिए चुनौती बड़ी है और यह ध्यान भी रखना होगा कि लोकसभा चुनावों के नतीजों से उत्साहित सपा-कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में इससे बड़ी जीत के लिए पूरी कमर कस कर मैदान में उतरेंगे। भाजपा के लिए यूपी में खतरा कितना बड़ा है, यह इससे ही समझा जा सकता है कि उसने राज्य में पिछले चुनाव के मुकाबले आधे के करीब सीटें तो गंवायी ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर भी पिछले चुनाव के मुकाबले करीब सवा तीन लाख वोटों से कम हो गया है।

सपा की रणनीति को देखें तो टिकट वितरण के दौरान अखिलेश कई बार अंतिम क्षणों में टिकटों में बदलाव कर रहे थे। इससे उनकी कुछ आलोचना भी हो रही थी। लेकिन अखिलेश, कांग्रेस के साथ मिलकर अपने पीडीए फॉर्मूले को हर हाल में अमल में लाने का फैसला कर चुके थे। बिना किसी दबाव में आए उन्होंने जहां जरूरत समझी वहां पूरी छानबीन के साथ टिकटों में बदलाव किया। उन्होंने मुसलमानों की पैरवी करने के आरोपों से भी अपने दामन को बचाने की कोशिश की और हर बार की अपेक्षा इस बार सपा ने कम ही टिकट मुस्लिमों को दिए। टिकट वितरण के उनके इस पुख्ता फॉर्मूले के साथ सरकार की नाकामी के कई ऐसे मुद्दे थे जिसने इंडिया गठबंधन का रास्ता यूपी में आसान कर दिया। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की नाराजगी और पेपरलीक जैसे मुद्दों को गठबंधन ज्यादा बेहतर तरीके से जनता के सामने रख सका। रही सही कसर चार सौ सीटें आने पर संविधान में बदलाव की आशंका ने पूरी कर दी।

विपक्ष संविधान में बदलाव की आशंका को बेहतर तरीके से जनता के सामने रख सका। इससे बसपा से खिसक रहा उसका कुछ परंपरागत दलित वोटर सपा और कांग्रेस की तरफ चला गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से बने माहौल को भी भाजपा वोट में बदल नहीं सकी। चुनाव के लिए जुटने वाला संघ और संगठन भी इस बार प्रभावी नहीं दिखा। इस सबने राज्य में चुनाव परिदृश्य को पूरी तरह बदलकर रख दिया और यूपी के सहारे अकेले बहुमत का सपना संजोये भाजपा का सपना पूरा नहीं हो सका। टिकट वितरण में भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व अति आत्म विश्वास ने भारी लापरवाही बरती।

जनता क्या चाहे... कि सुनी जाए उसके भी मन की बात

शंकर अय्यर

लोकतंत्र का जादू 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में अभिव्यक्त हुआ है। यह जनादेश दरअसल एक ऐसे अभियान से उपजी आशंकाओं का प्रतिबिंब है, जो विचारों पर कम और पहचान व विचारधारा पर अधिक केंद्रित रहा। यह जनादेश कई अनुभवों का मिला-जुला रूप है। इसमें उन माता-पिता के अनुभव शामिल हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए लाखों रुपये खर्च किए, फिर भी अपने बच्चों को नौकरी के लिए संघर्ष करता हुआ देख रहे हैं। उन लोगों का अनुभव, जिन्होंने महामारी के दौरान अपने प्रियजनों को खो दिया। उन लोगों का अनुभव, जो सब्जियों व ईंधन की बढ़ती कीमतों के बावजूद सीमित आय से अपना घर चलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन किसानों का अनुभव जो खेती की बढ़ती लागत और खेतों से होने वाली आय में गिरावट का सामना कर रहे हैं और उन भाई-बहनों का अनुभव भी शामिल है, जो पेपर लीक का शिकार हुए।

यह जनादेश राजनेताओं को अंतर्दृष्टि देता है, तो सवाल भी पूछता है। चुनाव अभियान के दौरान तीन बच्चों की मां ने पूछा, क्या मुझे इस तथ्य पर वोट देना चाहिए कि डेढ़ हजार रुपये मेरे खाते में आ रहे हैं, या इस पर कि मेरा बेटा व बेटी दोनों बेरोजगार हैं। देश की जनता ने एक शानदार फैसला सुनाया है। वर्ष 2004 में चुनावी नतीजों के तुरंत बाद लालकृष्ण आडवाणी ने जनादेश की राज्य के जनादेशों के सामूहिकीकरण के तौर पर परिभाषित किया था। इस तरह से देखें, तो 2024 के चुनावी नतीजे एक तरह से आय के पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर स्थित लोगों की, जो सरकारी योजनाओं पर निर्भर भी हैं, गंभीर हताशाओं के समूह भी हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले राजग ने कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया और कई राज्यों ने भी महिलाओं की आय में मदद करने वाली योजनाएं शुरू कीं।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल-सबसे ज्यादा सीटों वाले जिन राज्यों के नतीजों में भाजपा की संख्या में गिरावट दिखी, वह दरअसल यहां के उन लोगों की अधूरी इच्छाओं का समूह ही है, जो आजीविका कमाने की अपनी

क्षमता में सम्मान और पहचान चाहते हैं। पिछले तीन साल में हुए हर जनमत सर्वे में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को रेखांकित किया गया। भाजपा ने विभिन्न स्रोतों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया और तर्क दिया कि नौकरियां पैदा हो रही हैं। नौकरियां पैदा हो रही हैं, इससे कोई इन्कार नहीं है, लेकिन उसी तरह इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि जो नौकरियां हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। सबसे बुरी बात यह है कि केंद्र व राज्यों में तीस लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, जो बेरोजगारी को लेकर तमाम शिकायतों के बावजूद भरे नहीं गए हैं। आय व रोजगार क्षेत्र की कमजोर वृद्धि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों में भी दिखती है। यह सच है कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यह भी सच है कि इस वृद्धि ने बीते मई में शेयर बाजार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। लेकिन यह भी सच है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था आठ फीसदी से ज्यादा की दर से बढ़ रही है, निजी अंतिम खपत, जो उपभोक्ताओं की उपभोग करने की क्षमता और इच्छा की माप है, महज चार फीसदी की दर से बढ़ रही है।

यह समृद्धि और अभाव के बीच के अंतर का प्रतिबिंब है। भारत के लिए चुनौतियों और अवसरों को रेखांकित करने वाला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश का 45 फीसदी कार्यबल कृषि में लगा है और यह इतनी बड़ी आबादी राष्ट्रीय आय के महज छठे हिस्से पर निर्भर है। यह वास्तविकता राज्यवार वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में परिलक्षित होती है। तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय तीन लाख रुपये से ज्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 80 हजार रुपये से कम, तो बिहार की 55 हजार रुपये से भी कम है। जिलेवार आंकड़ों में यह अंतर अधिक स्पष्ट होता है। बिहार के शिवहर में प्रति व्यक्ति आय 18,692 रुपये है। एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने कृषि में संलग्न लोगों को बेहतर आय वाली नौकरियों में स्थानांतरित करने के लिए नौकरियां पैदा करने के पवित्र वादे तो किए, लेकिन वे सभी पूरे नहीं हुए। ऐसे में, ताजा चुनावी नतीजे सरकारों को याद दिलाते हैं कि मतदाता बदलाव के लिए धैर्य रख सकते हैं, लेकिन उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। चुनाव से कुछ समय पहले एक बुजुर्ग की एक टिप्पणी मुझे याद आ रही है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या %400 पार% की कहानी असली है? उन्होंने जवाब के लिए इंतजार नहीं किया और कहा कि विपक्षी दल इस सरकार को नहीं हरा सकते, लेकिन देश की जनता को हल्के में मत लीजिए, वह सही समय पर बोलेगी।

लोगों ने दरअसल जो दिख रहा था और राजनीतिक दलों की जो मंशा थी, उस पर बात की। दिवंगत अरुण जेटली ने कहा था कि चुनाव केवल %गणित% नहीं, बल्कि %केमिस्ट्री% के बारे में भी होते हैं। इस चुनाव में कई राजनीतिक दल केमिस्ट्री को भूलकर जाति और नकद के गणित का सहारा लेने में लगे रहे। फैजाबाद के रूप में भाजपा को वह सीट खोनी पड़ी, जहां अयोध्या स्थित है। यह बताता है कि केवल आस्था नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य की आशा है, जो ईवीएम पर बटन दबाती है। राजनीतिक दलों ने दूसरे दलों व नेताओं के बीच केमिस्ट्री के बारे में बात तो की, लेकिन लोगों के साथ बेहतर केमिस्ट्री बनाने में चूक की। यह जनादेश जनमत की व्यापक लामबंदी और संगठनात्मक ताकत के बारे में भी है। जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों ने चतुर चालें चलों तो गलतियां भी कीं। चुनाव का विश्लेषण होगा, तो जातियों, प्रत्याशियों और साजिशों पर भी बात होगी। लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखती है राजनीतिक दलों की अपनी शिकायतें सुनने और उनके समाधान ढूंढने की क्षमता। जनता बड़े-बड़े दावे नहीं सुनना चाहती, वह तो सिर्फ यह चाहती है कि उसकी भी सुनी जाए और यही इस जनादेश का सबसे बड़ा सबक है।

लोकसभा चुनाव में मेहनत से मिली विपक्ष को कामयाबी

रशीद किदवई

आम तौर पर ऐसा नहीं होता है कि कोई दल या गठबंधन सत्ता से वंचित रह जाए, फिर भी उसके खेमे में उल्लास हो। इसी तरह ऐसा भी नहीं होता कि कोई दल या गठबंधन जीत जाए या सरकार बनाने की स्थिति में हो, पर वह हताशा में दिखे। इस बार यही होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव परिणाम दोनों पक्षों के लिए बहुत कुछ सीख लेने का अवसर है। सत्तारूढ़ दल ने 400 से अधिक सीटें लाने का दावा किया था, जिसे मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी खूब हवा दी थी। इसीलिए उस खेमे में निराशा का माहौल है। किसी भी पार्टी के लिए तीसरी बार लगातार चुनाव जीतना एक मुश्किल काम होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 का चुनाव आशा के आधार पर जीता था। अगले चुनाव में राष्ट्रवाद का भावनात्मक मुद्दा उठाया गया। इस बार इस तरह का कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। मोदी का कोई विकल्प नहीं है, इस आधार पर भाजपा ने 2024 का चुनाव लड़ा। उनके भाषणों में भी नकारात्मकता दिखी और उन्होंने क्षत्रपों को किनारे करने का प्रयास भी किया। ऐसा इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस भी करती थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। इस परिणाम से राहुल गांधी बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाया है। विषम परिस्थितियों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ाना एक बड़ी उपलब्धि है। राहुल गांधी की दो यात्राओं तथा बेबाकी से मुद्दों को उठाने का लाभ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिला है। राजस्थान में कांग्रेस ने वापसी की है। अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होतीं, शायद ऐसे नतीजे नहीं आते। महाराष्ट्र में तोड़-फोड़ और अस्थिरता की जो राजनीति हुई, मुझे लगता है कि उसका संदेश अच्छा नहीं गया। भावनात्मक आधार पर विपक्षी गठबंधन को लोगों का समर्थन मिला। बंगाल में भी चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया गया और जमीनी हकीकत से परे रह कर चुनाव लड़ा गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा जातिगत समीकरण को इस बार साधने में विफल रही। राहुल गांधी को घेरने का प्रयास भी काम नहीं आया। वे केरल से चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा ने बार-बार उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ता के हाथों हार होना एक बड़ा झटका है। राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को घेर कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास भी बहुत से मतदाताओं को रास नहीं आया। बहरहाल, इस परिणाम से राहुल गांधी बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाया है। विषम परिस्थितियों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ाना एक बड़ी उपलब्धि है। राहुल गांधी की दो यात्राओं तथा बेबाकी से मुद्दों को उठाने का लाभ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिला है। कांग्रेस पहले भी चुनाव हारी है, पर उसका मनोबल नहीं टूटता था, लेकिन 2014 और 2019 में उसका मनोबल टूट गया था। ये परिणाम उसके लिए प्रभावी संजीवनी की तरह हैं। पूरे देश में एक नेता के तौर पर राहुल गांधी को स्वीकृति मिली है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने शानदार उपस्थिति दर्ज की है। ममता बनर्जी ने पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा के आक्रामक प्रचार को ध्वस्त किया है। अखिलेश यादव ने राज्य के जातिगत समीकरण को अच्छी तरह समझा और अनेक जातियों के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। बसपा के लिए इस चुनाव का संदेश यही है कि जनता अघोषित राजनीतिक सांठ-गांठ को पसंद नहीं करती है। आगे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, जहां एनडीए गठबंधन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

बैचलरेट पार्टी के लिए तलाश रहे बेहतरीन डेस्टिनेशन्स, तो ये जगह आपको नहीं करेंगी निराश

ऐसे में अगर आपकी भी जल्द ही शादी होने वाली है और आप बैचलरेट पार्टी के लिए किसी शानदार जगह की तलाश में हैं। ऐसे में आप यहां पर बैचलरेट पार्टी के अलावा कई तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज में भी शामिल हो सकते हैं।

इन दिनों शादी से पहले सिर्फ प्री वेडिंग का ही नहीं बल्कि बैचलरेट पार्टी का भी ट्रेंड तेजी से चल रहा है। ऐसे में अगर आपकी भी जल्द ही शादी होने वाली है और आप बैचलरेट पार्टी के लिए किसी शानदार जगह की तलाश में हैं। जहां पर आप अपने हर पल को यादगार बनाना चाहते हैं। तो यह आर्टिकल आपके लिए है। हांलाकि इसके लिए कई लोगों की पहली पसंद गोवा होती है। लेकिन आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको गोवा से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत डेस्टिनेशन्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं।

आपको बता दें कि यह जगह अपनी खूबसूरत नजारों के लिए दुनियाभर में फेमस हैं। ऐसे में आप यहां पर बैचलरेट पार्टी के अलावा कई तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज में भी शामिल हो सकते हैं। इन जगहों पर की गई बैचलरेट पार्टी आपको हमेशा याद रहेगी। तो आइए जानते हैं इन खूबसूरत डेस्टिनेशन्स के बारे में...

ग्रीस

अगर आप किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन की तलाश में हैं, तो बता दें कि इसके लिए ग्रीस से बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है। आप यहां के खूबसूरत गांव, बीच, लाजवाब खानपान, बीच पार्टीज़, सनसेट व्यू और कभी न थमने वाली नाइट लाइफ जैसी कई चीजों को एक्सपीरियंस कर

सकते हैं। साथ ही अगर आपको फोटोज क्लिक कराने के शौक है, तो यहां की कई बेहतरीन लोकेशन पर फोटोज क्लिक करवा सकते हैं।

तुर्की

प्री वेडिंग के साथ ही बैचलरेट पार्टी के लिए तुर्की भी काफी डिमांड में है। यहां पर कई बहुत प्यारे लोकेशन्स हैं। आपको बता दें कि यहां की हर एक जगह आपको जादुई दुनिया में होने का एहसास कराती है। इसके साथ ही नेचर लवर्स से लेकर एडवेंचर लवर्स तक के लिए कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं। समुद्र के किनारे पर बसा तुर्की में सनसेट का नजारा मिस करने की गलती नहीं करनी चाहिए।

अजरबेजान

अजरबेजान का कैपिटल बाकू भी बैचलरेट पार्टी के लिए एक बेहतरीन लोकेशन हो सकती है। ऐसे में आप यहां पर बैचलरेट पार्टी के अलावा अपनी गैंग के साथ कई तरह के एडवेंचर भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो आपको यहां पर घूमने के लिए कई बेहतरीन जगह मिल जाएंगी। ऐसे में फन और रिलैक्स दोनों के लिहाज से यह च्वॉइस एकदम परफेक्ट है।

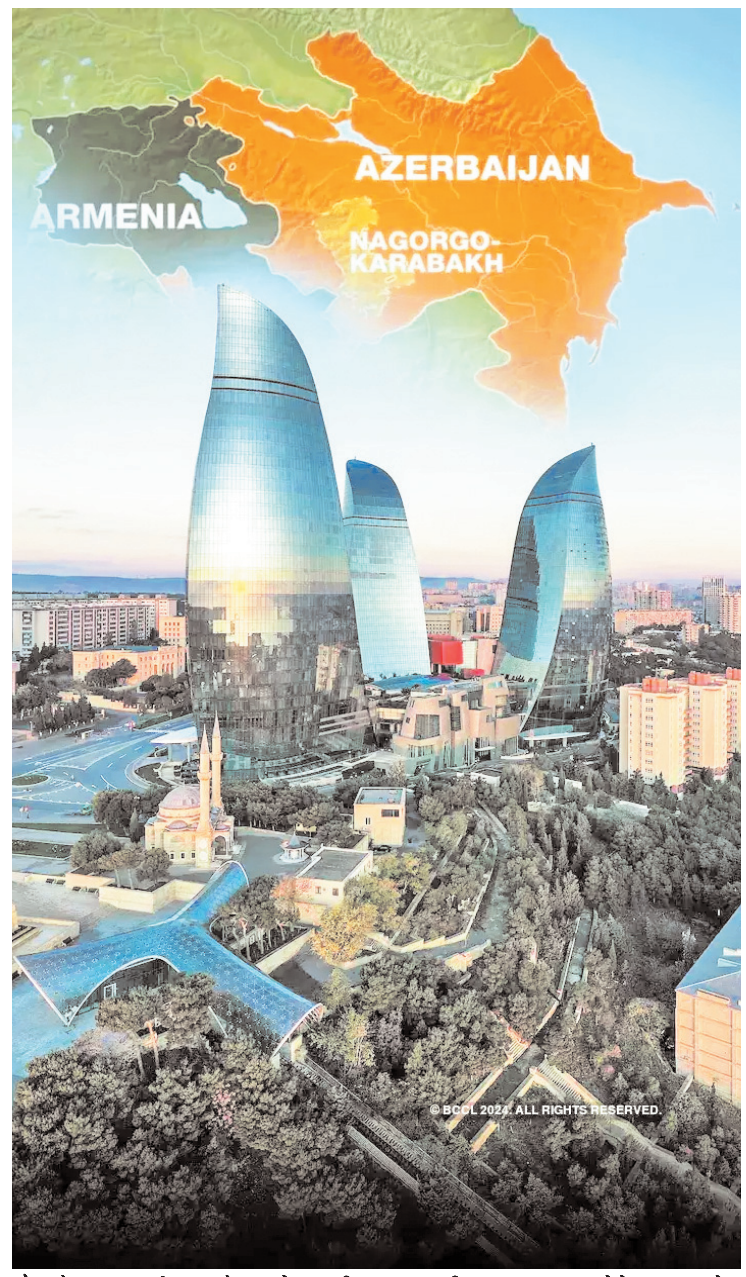

इंडोनेशिया

वहीं अगर आप थोड़े बजट में बैचलरेट पार्टी को निपटाना चाहती हैं, तो इंडोनेशिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यह एक शांत और बेहद खूबसूरत जगह है। इंडोनेशिया में करीब 17,000 आईलैंड्स हैं। ऐसे में आप यहां पर मौज-मस्ती के अलावा ढेर सारा

बंज़ी जम्पिंग करने के लिए बेस्ट हैं ये जगह, एक बार जरूर ट्राई करें

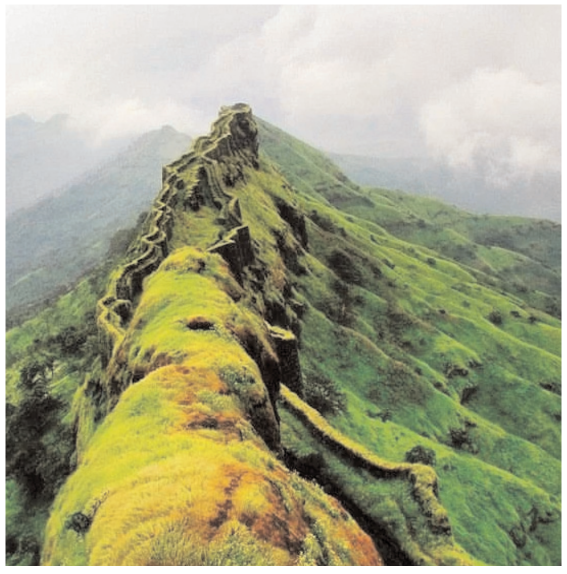

एडवेंचर एक्टिविटी करने के शौकीन लोग ट्रैकिंग, कैपिंग, स्काई डाइविंग, रिवर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा लेने के लिए अलग-अलग जगह जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप भी एडवेंचर लवर हैं, तो आपको बंजी जंपिंग का मजा लेने जरूर जाना चाहिए। ये एक बेहद तूफानी एक्टिविटी है। जिसे करने से पहले हर किसी का पसीना छूट जाता है। यहां उन जगहों के बारे में बता रहे हैं बंजी जंपिंग के लिए बेस्ट प्लेस।

लोनावला

लोनावला घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। इस जगह पर लोग वीकेंड पर पहुंचते हैं और एंजॉय करते हैं। ये जगह बंजी जंपिंग के लिए भी फेमस है। यहां 45 मीटर ऊपर से बंजी जंपिंग कराई जाती है। चार से पांच मिनट में पूरी होने वाली ये जंप आपको हमेशा याद रहेगी। बंजी जंपिंग करने के लिए यहां पर एक ऐज लिमिट सेट है।

ऋषिकेश

ऋषिकेश में होने वाली बंजी जंपिंग खूब फेमस है। यहां मोहन चट्टी में बंजी जंपिंग करवाई जाती है। ये 83 मीटर ऊपर चोटी पर है। ऐसे में आपको यहां पर प्रति व्यक्ति लगभग 3500 से 4000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। इस जगह पर बंजी जंपिंग एक्सपीरियंस करने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। यहां पर आप कई दूसरी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं।

बेंगलुरु

बेंगलुरु में भी बंजी जंपिंग करवाई जाती है। यहां क्रेन से जंप कराई जाती है। यहां पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर 80 से लेकर 130 फीट की ऊंचाई से जंप कराई जाती है। इस जगह पर भी एक्टिविटी का अलग मजा है।

भीड़-भाड़ नहीं चाहिए तो में इन शानदार हिल स्टेशन को बनाएं प्लान

आज के समय में सभी को घूमना-फिरना लगभग हर किसी को पसंद होता है। जब भी लोग कहीं घूमने जाते हैं, तो वे अपनी पसंदीदा जगह घूमने के लिए निकल जाते हैं। अगर आप भी ऐसी कोई जगह की तलाश कर रहे हैं, जहां भीड़-भाड़ न हो, शांत वातावरण हो। इसलिए कई लोग खूबसूरत जगह के साथ-साथ हिल स्टेशन की तलाश करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही हिल स्टेशन के बारे में बताएंगे।

मुनस्यारी

उत्तराखंड की हसीन वादियों में स्थित यह हिल स्टेशन बेहद खूबसूरत है। अगर आप जून- जुलाई में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मुनस्यारी आप जरुर जा सकते हैं। यह समुद्र तल से करीब 7 हजार से भी अधिक फीट की ऊंचाई पर स्थित मुनस्यारी एक शांत और रोमांटिक हिल स्टेशन माना जाता है। यहां आप पार्टनर के साथ सुकून का पल बिता सकते हैं। मुनस्यारी में स्थित बिर्थी झरना, पंचाचूली चोटियां, मदकोट गांव, दरकोट गांव, बेटुली धार, माहेश्वरी कुंड और खलिया टॉप जैसी शानदार जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

कसोल

यह हिल स्टेशन शिमला, कुल्लू-मनाली, धमर्शाला या डलहौजी जैसे हिल स्टेशनों पर अक्सर भीड़-भाड़ रहती है। कसोल एक ऐसा हिल स्टेशन है, जहां भीड़ कम रहती है और यहां की खूबसूरती का अलग ही नजारा होता है। यहां पर ऊंचे-ऊंचे पहाड़, घने जंगल, देवदार के बडे-बड़े पेड़ और झील-झरने के बीच में सुकून का पल बिता सकते हैं।

माथेरान

यह एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन एक्सप्लोर करने की बात होती है, तो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र का माथेरान हिल स्टेशन भी खूबसूरती के मामले कम नहीं है। जुलाई के दौरान माथेरान की खूबसूरती चरम पर होती है। यहां आप सुकून के पल बिता सकते हैं। माथेरान को टॉप मानसून डेस्टनेशन भी माना जाता है। यहां आप इसा पॉइंट, चार्लोट झील, मंकी पॉइंट, शिवाजी सीढ़ी और पैनोरमा पॉइंट जैसी शानदार जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

पेलिंग

यह हिल स्टेशन नॉर्थ इस्ट इंडिया में मौजूद है। सिक्किम में स्थित पेलिंग भी एक ऐसा हिल स्टेशन है, जहां घूमना हर किसी का सपना हो सकता है। समुद्र तल से करीब 7 हजार से भी अधिक फीट की ऊंचाई पर मौजूद पेलिंग प्रकृति प्रेमी के लिए हसीन जन्नत है। पेलिंग में आप सुकून का पल बिताने के साथ-साथ एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकती है।

अगस्त में एक्सप्लोर करें तमिलनाडु की खूबसूरती

तमिलनाडु एक बेहद खूबसूरत और तमाम तरह की खूबियां समेटे हुए राज्य है। इस जगह को फुल पैकेज कहा जा सकता है क्योंकि यहां हिल स्टेशन भी हैं और शानदार बीच भी। मतलब हर तरह के घूमन्तू यहां आकर एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक तमिलनाडु को नहीं किया है एक्सप्लोर तो आईआरसीटीसी के साथ अगस्त में बना लें प्लान।

तमिलनाडु, भारत का बेहद खूबसूरत राज्य, जहां घूमने-फिरने वाले ठिकानों की कोई कमी नहीं। आप यहां आकर हर तरह की मौज-मस्ती कर सकते हैं। नेचर लवर हैं या फिर एडवेंचर के शौकीन। तमिलनाडु में हर तरह के ऑप्शन्स मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया है, तो अगस्त में बना सकते हैं प्लान। आईआरसीटीसी लेकर आया है

बजट में यहां घूमने का मौका।

पैकेज की अवधि- 5 रात और 6 दिन

ट्रैवल मोड- फ्लाइट

डेस्टिनेशन कवर्ड- मदुरै, रामेश्वरम, तंजव्वुर, कुंबाकोनम

मिलेंगी यह सुविधाएं

1. रुकने के लिए होटल की सुविधा मिलेगी।
2. इस टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी।
3. आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की भी सुविधा मिलेगी।

यात्रा में लगेगा इतना शुल्क

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 39,850 रुपए चुकाने होंगे।
2. वहीं दो लोगों को 30,500 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।
3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 29,250 रुपए का शुल्क देना होगा।
4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 26,800 और बिना बेड के 22,600 रुपए देने होंगे।

ट्वीट करके दी जानकारी

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप तमिलनाडु के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज

जून की गर्मी में ओढ़ना पड़ेगा कंबल, सबसे ठंडी हैं ये 3 जगहें, बनाएं घूमने का प्लान

भीषण गर्मी से बचने के लिए आप भी पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ ठंडी जगहें, जहां आप जा सकते हैं। यहां आपको सुंदर प्रकृतिक नजारे देखने को मिलेंगे।

गर्मी का कहर जारी है पूरे देश में, ऐसे में कहीं बाहर ठंडी जगह पर घूमने का मन बहुत करता है। इस समय बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं। हीटवेव और तेज धूप से बचने के लिए लोग घर पर ही रहना पसंद कर रहे है। जो लोग इस तपती गर्मी में भी घूमने के लिए बाहर का प्लान बना रहे हैं। उन लोगों को हम कुछ खास लोकेशन की लिस्ट लेकर आए है। गर्मी में इन ठंडी जगहों पर जाने पर सर्दी का एहसास होगा। चलिए इन जगहों के बारे में बताते हैं।

कामशेत

जो लोग घुमक्कड़ हैं उन लोगों को यह जगह बहुत ही पसंद आएगी। इस जगह को भारत की पैराग्लाइडिंग राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर आप पुणे से जा रहे हैं, तो आपको यहां पहुंचने के लिए 45 किमी की दूरी तय करनी पड़ेगी। मुबंई से यह 110 किमी है। पश्चिमी घाट से और पर्वतों से घिरी इस जगह का मौसम आपको जून में भी ठंडा अहसास कराएगा।

कैसे पहुचें

वायु मार्ग- यहां जाने के लिए सबसे पहले कामशेत से 55 किमी की दूरी पर स्थित पुणे में हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद, आप कामशेत के लिए बस, टैक्सी या ट्रेन ले सकते हैं।

ट्रेन - कामशेत का निकटतम रेलवे स्टेशन लोनावाला में है। एक बार जब आप स्टेशन से बाहर निकलें, तो स्थानीय टैक्सी किराए पर लें क्योंकि कामशेत केवल 17 किमी दूर है।

सड़क- आप या तो पुणे से कामशेत तक राज्य तक जाने वाली बसों से यात्रा कर सकते हैं, या ड्राइव भी कर सकते हैं। कामशेत राजमार्ग के माध्यम से पुणे के साथ-साथ मुंबई से भी जुड़ा हुआ है।

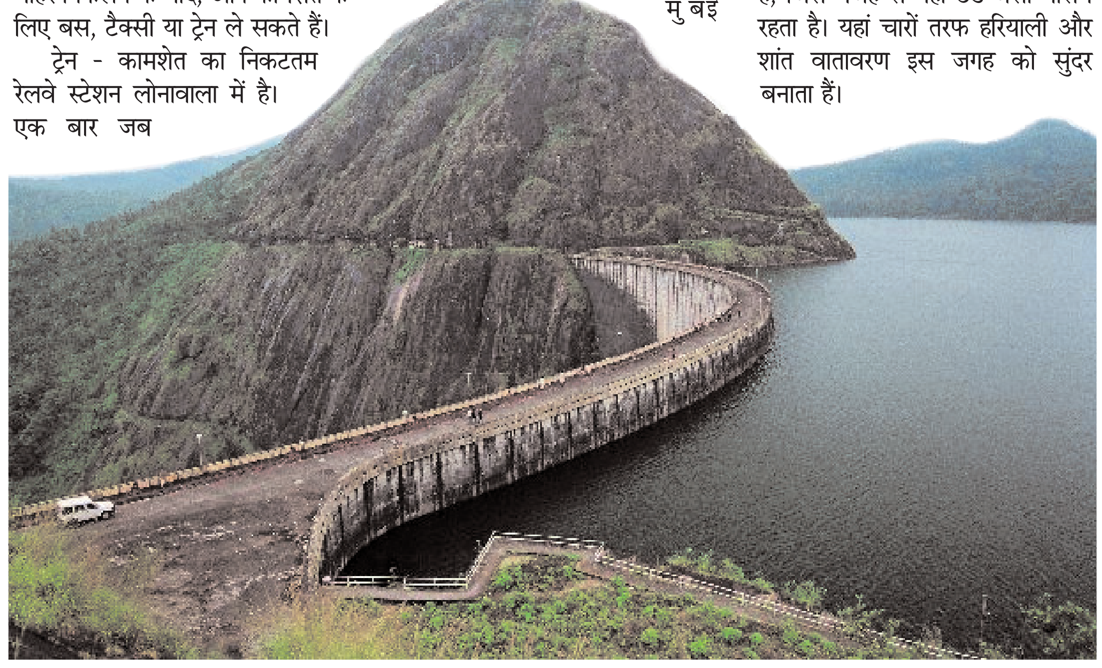

कुमारकोम

कुमारकोम केरल का एक छोटा और खूबसूरत नगर है। कोट्टायम से लगभग 16 किमी की दूरी पर स्थित है। यह घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। वैसे तो केरल में जून महीने में मौसून आ जाता है, जिस वजह से यहां ठंड जैसा मौसम रहता है। यहां चारों तरफ हरियाली और शांत वातावरण इस जगह को सुंदर बनाता हैं।

कैसे पहुंचे

वायु मार्ग - कुमारकोम का निकटतम हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह लगभग 70 किमी दूर है।

रेल द्वारा - कुमारकोम से निकटतम रेलवे स्टेशन कोट्टायम है, जो लगभग 15 किमी दूर स्थित है।

इडुक्की

इडुक्की पश्चिमी घाट के ऊंचाई पर स्थित है। हर साल यहां सुखद जलवायु का आनंद लिया जा सकता है। इस जगह को गर्मियों की छुट्टियों के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। यहां ऊबड़-खाबड़ पहाडियों और घने जंगल वनस्पतियों और जीवों का घर हैं। अगर आप इडुक्की घूमने जा रहे हैं तो इन जगहों पर जरुर जाएं, आर्क बांध, हिल व्यू पार्क, कोलमावु बांध, नदुकानी, पेनावु, अनाकार्रा, पेरियार नेशनल पार्क और मुर्रिकैडी।

कैसे पहुंचे

-निकटतम हवाई अड्डा- कोचीन अंतर्राष्टीय हवाई अड्डा (95 किमी)

-निकटतम रेलवे स्टेशन- एर्नाकुलम जंक्शन (100 किमी)

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हो सकते हैं

नईदिल्ली। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने और पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है। जल्द ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें लोकसभा में कांग्रेस के नेता का फैसला किया जाएगा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की खुलकर मांग की है। 4 जून को आये जनादेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए तैयार है। एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 293 सीटें जीती हैं, जो 543 सदस्यीय सदन में 272 के बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है, जिससे मोदी के लिए लगातार तीसरी बार शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है, जो 1962 के बाद से किसी भी सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए पहली बार है। बुधवार को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सर्वसम्मति से मोदी को अपना नेता चुना।

अग्निवीर योजना पर विचार की जरूरत : केसी त्यागी

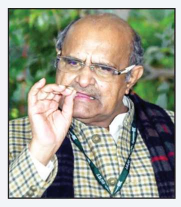

पटना। नीतीश कुमार की जेडीयू ने एक राष्ट्र, एक चुनाव और यूसीसी का समर्थन किया है जिन एजेंडे पर भाजपा वर्षों से जोर दे रही है और लागू करना चाहती है। हालांकि, जेडीयू अग्निवीर योजना की समीक्षा चाहती है, जिसके बारे में उसका मानना है कि इसका असर चुनावों पर पड़ा। अग्निपथ योजना, जिसे जून 2022 में शुरू किया गया था, युवाओं को चार साल के लिए भर्ती किया जाता है, जिसके बाद उनमें से 25% को बरकरार रखा जाएगा और बाकी को रिहा कर दिया जाएगा - एक ऐसा खंड जिसने सेना के उम्मीदवारों को परेशान कर दिया है। केसी त्यागी ने यह बयान देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। जेडीयू, जिसका समर्थन एनडीए सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, ने भी कहा है कि उसे समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह सभी हितधारकों के साथ बातचीत चाहता है।

चंद्रबाबू नायडू 12 को लेंगे आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ

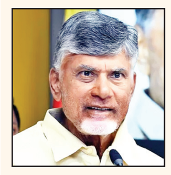

विजयवाड़ा। तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। अब वह 12 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले यह कायक्रम 9 जून को होना था। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। नायडू के शपथ लेने की तारीख में बदलाव की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को बताया जा रहा है। वे लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में टीडीपी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। 135 सीटें जीत कर टीडीपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। वहीं, जनसेना ने 21 सीटें जीतीं। भाजपा आठ सीटों पर जीतने में सफल रही। वर्तमान सत्तारूढ़ दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मात्र 11 सीटों पर सिमट गई है। वहीं, लोकसभा की अधिकांश सीटें भी एनडीए की झोली में गई हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को जमानत

नई दिल्ली। चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को जमानत मिल गई है। यह आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। कोर्ट के समन जारी करने के बाद तारीख से पहले ही कार्ति चिदंबरम पेश हो गए थे। जिसको देखते हुए ईडी और सीबीआई की विशेष जज कावेरी बावेजा ने चिदंबरम को जमानत दे दी। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट के आधार पर कार्ति चिदंबरम को समन जारी किया था। कोर्ट ने एक लाख रुपये को निजी मुचलके और इतनी धनराशि पर आरोपी को जमानत दी है। ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। मामले में कार्ति चिदंबरम के अलावा 3 अन्य लोगों को ईडी ने आरोपी बनाया था। उस समय कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। मामले में सीबीआई के मामला दर्ज करने के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी केस दर्ज किया गया था।

मेरा राजनीतिक भविष्य कैसा होगा, नहीं जानताः अधीर रंजन

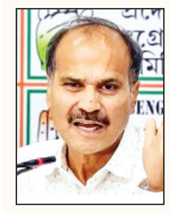

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बहरमपुर संसदीय क्षेत्र से हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पांच बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वह नहीं जानते कि उनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख अधीर चौधरी को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने 85,000 से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया। श्री चौधरी की पराजय के साथ ही कांग्रेस ने बहरमपुर पर अपनी राजनीतिक पकड़ खो दी, जो राज्य में कांग्रेस का अंतिम गढ़ था। पार्टी को केवल एक सीट मालदा दक्षिण पर जीत मिली है। अपने बहरमपुर आवास पर एक निजी चैनल से बात करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि उन्हें आशंका है कि आने वाला समय उनके लिए कठिन होगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में मेरे लिए मुश्किलें खड़ी होंगी और मुझे नहीं पता कि उनसे कैसे पार पाया जाये।

सघन चुनाव प्रचार से संकेत मिलता है कि केजरीवाल गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं : कोर्ट

नईदिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने जिस तरह सघन (चुनाव) प्रचार किया एवं अन्य संबंधित गतिविधियों में भाग लिया, उससे संकेत मिलता है कि वह किसी गंभीर या 'जानलेवा' बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं।

केजरीवाल को एक और झटका देते हुए अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग संबंधी उनका आवेदन बुधवार को खारिज कर दिया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा, ''अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह सघन प्रचार किया तथा संबंधित बैठकें व कार्यक्रम किये, जैसा कि बहस के दौरान बताया गया, वे संकेत देते हैं कि वह किसी गंभीर या 'जानलेवा' बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं, ऐसे में वह इस लाभ के हकदार नहीं हैं।''

न्यायाधीश बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक के लिए बढ़ा दी। अदालत इस मामले में वैधानिक जमानत की मांग संबंधी उनकी अर्जी पर सात जून को सुनवाई करेगी। अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उच्च कीटोन स्तर या वजन के कथित रूप से घटने से 'मधुमेह कीटोएसिडोसिस' हो सकता है, परीक्षण कराने की खातिर अंतरिम जमानत प्रदान करने का आधार 'चिकित्सीय जरूरत से भी अधिक कमजोर है।'

न्यायाधीश ने कहा, '' प्रत्यक्ष तौर पर, जैसा कि आवेदक ने अनुमानित बीमारी की 'नैदानिक जांच' के लिए अंतरिम जमानत की मांग की हैः ऐसा कोई कारण जान नहीं पड़ता है कि हिरासत में रहने के दौरान आवेदक के परीक्षण क्यों नहीं कराये जा सकते हैं?''

न्यायाधीश ने हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन को न्यायिक हिरासत के दौरान उनकी चिकित्सा जांचों का ध्यान रखने का निर्देश दिया। शनिवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया था कि उन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार किया लेकिन 'अब जब आत्मसमर्पण करना है तो वह अचानक बीमार होने का दावा कर रहे हैं।''

नौ जून को मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ, तीसरी बार बनाएंगे सरकार

नईदिल्ली। एनडीए की जीत के बाद केंद्र में एक बार फिर सरकार गठन की तैयारी शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से खबर है कि 9 जून को शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें, इससे पहले शपथ ग्रहण की तारीख 8 जून को तय की गई थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि अब तिथि में बदलाव कर इसे नौ जून कर दिया गया है।

गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। चुनाव नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि उसके पास भी पूर्ण बहुमत से 32 सीटें कम हैं। ऐसे में बीजेपी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार गठन कर रही है। वहीं टीडीपी और जेडीयू का कहना है कि उन्हें हर चार सांसद पर एक मंत्री पद चाहिए। ऐसे में मोदी कैबिनेट 3.0 में अगर सरकार इस शर्त पर बनती है तो टीडीपी को चार और जेडीयू को तीन विभाग देना होगा। इसके अलावा जेडीएस के कुमारस्वामी भी दो मंत्री पद अपने बेटे और दामाद के लिए मांग रहे हैं।

इधर, नयी सरकार के गठन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी ने नेताओं ने बैठक की। बैठक में सरकार गठन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस बैठक में भावी मंत्रिपरिषद के गठन में एनडीए के घटक दलों की भागीदारी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।

इधर, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने कहा है कि वो सहयोगी दलों की हर जायज मांग को मानेगी लेकिन किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। बयान में कहा गया है कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करेगी। खबर है कि बीजेपी निर्दलीय और छोटे दलों के भी संपर्क में है। बीजेपी ने कहा है कि पार्टी गैर जरूरी मांगों के आगे नहीं झुकेगी।

मजबूर नहीं मजबूत सरकार...सहयोगियों के सामने मोदी ने खींची लक्ष्मण रेखा

चुनाव परिणाम आने के बाद से ही ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि देश के अंदर ही नहीं बीजेपी के अंदर भी भूचाल आने वाला है। ऐसे दावे और खबरें आप लगातार देख रहे होंगे कि पीएम मोदी बड़े दबाव में हैं। अब वो कोई कड़ा फैसला नहीं ले सकते क्योंकि सरकार की चाबी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथों में है। दोनों पार्टी अगर सपोर्ट हटा लेगी तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। मीडिया में भी ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अटल बिहारी वायपेयी के 24 पार्टियों वाली गठबंधन सरकार से इसकी तुलना की जा रही है। उस दौर में पार्टियां इतना दबाव बनाकर रखती थी कि न तो अटल बिहारी वाजपेयी, न ही आडवाणी और न ही बीजेपी की पूरी मशीनरी कोई कड़े और बड़े फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पाई। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के सहारे सरकार चलाना पड़ा। डेवलमपेंट का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी से बचने के उपाय जैसे कार्य शुरू हुआ था।

ऐसा बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का आगे का प्लान यूसीसी और अन्य बड़े फैसले नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुमत मोदी के पास नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू नहीं हो पाएगा। धारणा बनाई जा रही है कि पीएम मोदी अब बैकफुट में आ जाएंगे। वो मंदिरों में नहीं जाएंगे और पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह इफ्तार पार्टी में नजर आएंगे। इसके साथ ही दावा किया जाने लगा कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो बार्गेनिंग करने वाली पार्टियां इस बार खुलकर अपनी मांगे रखेंगी। जिसके कारण बीजेपी बड़े फैसले नहीं ले पाएगी। लेकिन सारे के सारे अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है। जैसे मानों प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मोदी के ऊपर कोई दबाव बना नहीं सकता। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सहयोगियों के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी है।

गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे विभागों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। इसके साथ ही स्पीकर के पद पर भी पार्टी कोई समझौता नहीं करने वाली है। बीजेपी टीडीपी को डिप्टी स्पीकर पोस्ट दे सकती है। टीडीपी ने वित्त और आईटी मंत्रालय जैसे विभागों की मांग की थी। लेकिन टीडीपी को सिविल एविएशन, स्टील जैसे संभावित मंत्रालय दिए जा सकते हैं। इंफ्रा, कल्याण, कृषि विभाग बीजेपी अपने पास रखेगी। जदयू के लिए पंचायती राज, ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय दिए जा सकते हैं। शिवसेना के लिए भारी उद्योग की संभावना है। 2014 में देश में सत्ता में आने के बाद से मोदी किसी के दवाब में नहीं आए। गुजरात में सीएम रहते हुए भी उनकी कार्यशैली इसी तरह की नजर आई। गुजरात दंगा के आरोपों से लेकर अमेरिका के वीजा नहीं देने तक सभी से मोदी ने अपनी शैली में ही निपटा। यूरोप और अरब दुनिया के कई देशों ने भी दबाव बनाया लेकिन कुछ काम नहीं आया।

सपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रियंका गांधी ने जताया आभार, बोलीं-

आप प्रताड़ित हुए लेकिन झुके नहीं, रुके नहीं

लखनऊ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कहा कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़े और लोकतंत्र के प्रहरी बने। इसको लेकर उन्होंने एक्स पोस्ट किया है। प्रियंका ने लिखा कि यूपी कांग्रेस के मेरे सभी साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में कड़ी मेहनत करते हुए देखा, आप झुके नहीं, आप रुके नहीं, कठिन से कठिन दौर में आपने लड़ने की हिम्मत दिखाई। आपको प्रताड़ित किया गया, आप पर फर्जी मुक़दमे लगाये गये, जेल में डाला गया, बार-बार नज़रबंद किया गया मगर आप डरे नहीं। कई नेता डर के चले गये, आप टिके रहे।

प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे गर्व है आप पर और यूपी की जागरूक जनता पर, जिसने इस देश की गहराई और सच्चाई को समझा और हमारे संविधान को बचाने का ठोस संदेश पूरे भारत को दिया। आपने आज की राजनीति में एक पुराना आदर्श फिर से स्थापित किया है- कि जनता के मुद्दे सर्वोपरि हैं, इनको नकारने की क़ीमत भारी होती है। चुनाव जनता का है, जनता ही लड़ती है, जनता ही जीतती है। उन्होंने अखिलेश यादव, डिंपल यादव और रामगोपाल यादव को टैग करते हुए लिखा कि आपको और समाजवादी पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को यूपी के नतीजों के लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। भीषण परिस्थितियों में हम सबने मिलकर एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जमीन पर कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ताओं ने हिम्मत से जनता के मुद्दों, सामाजिक न्याय और संविधान की आवाज उठाई। तमाम धमकियों व दमन के बावजूद वे एकजुट होकर लोकतंत्र के प्रहरी बने और बूथ-बूथ पर खड़े रहे। आप सबकी कड़ी मेहनत के चलते हमारी एकजुटता व मुद्दों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में जनता ने भरोसा दिखाया है। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय जनता। जय संविधान।

खेल
प्रमुख समाचार

स्टोइनिस के शानदार प्रदर्शन से आस्ट्रेलिया ने ओमान को हराया

ब्रिजटाउन। मार्कस स्टोइनिस के आक्रामक अर्धशतक और तीन विकेट की बदौलत गत चैम्पियन आस्ट्रेलिया ने टी20 विश्व कप में अपने अभियान का आगाज बृहस्पतिवार को ओमान पर 39 रन से जीत के साथ किया। स्टोइनिस ने 36 गेंद में नाबाद 67 रन बनाये जिसकी मदद से आस्ट्रेलिया ने पांच विकेट पर 164 का स्कोर बनाया। डेविड वॉर्नर ने भी 56 रन की पारी खेली। इसके बाद स्टोइनिस ने तीन ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट चटकाये। ओमान की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 125 रन ही बना सकी। आस्ट्रेलिया के लिये नाथन एलिस ने 28 रन देकर और आईपीएल स्टार मिचेल स्टार्क ने 20 रन देकर दो दो विकेट लिये।

स्टार्क ने ओमान की पारी की तीसरी गेंद पर प्रतीक अठावले (0) को आउट कर दिया। मैदानी अंपायर द्वारा नॉट आउट दिये जाने के बाद आस्ट्रेलिया ने डीआरएस लिया जिसमें फैसला उसके पक्ष में रहा। एलिस ने कश्यप प्रजापति (सात) को पगबाधा आउट किया जिस पर ओमान ने रिव्यू लिया लेकिन नाकामी हाथ लगी। स्टोइनिस ने पावरप्ले की आखिरी गेंद पर ओमान के कप्तान आकिब इलयास (18) को आउट किया जिनका कैच विकेट के पीछे मैथ्यू वेड ने लपका। स्टोइनिस ने जीशान मकसूद (1) को आठवें ओवर में पवेलियन भेजा। अयान खान ने 30 गेंद में दो चौकों और दो छक्कों की मदद से 36 रन बनाये और सातवें विकेट के लिये 37 रन की साझेदारी की। इससे पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर आस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 164 रन बनाये। ट्रेविस हेड (12) और कप्तान मिचेल मार्श (14) सस्ते में आउट हो गए। अनुभवी हरफनमौला ग्लेन मैक्सवेल का खराब फॉर्म जारी रहा जो खाता भी नहीं खोल सके। मेहरान की गेंद पर इलयास ने उनका बेहतरीन कैच लपका। स्टोइनिस और वॉर्नर ने चौथे विकेट के लिये 64 गेंद में 102 रन जोड़े।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 75 हजार के पार निफ्टी 22,819 पर बंद

नईदिल्ली। लोक सभा चुनाव के नतीजों से सहमी शेयर बाजार की गाड़ी लगभग पटरी पर लौट गई और गुरुवार को इक्विटी बेंचमार्क लगातार दूसरे दिन पॉजिटिव रुख में बंद हुए। निवेशक चौंकाने वाले चुनाव नतीजों से लगभग उबर गए हैं और गठबंधन की सरकार के गठन से उनके बीच घबराहट कम हुई है। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज शानदार तेजी के साथ 75,078.70 अंक पर खुला और कारोबार के दौरान यह 75,297.73 अंक के इंट्रा-डे हाई लेवल तक पहुंच गया था। अंत में सेंसेक्स 0.93 प्रतिशत या 692.27 अंक उछलकर 75,074.51 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आज 0.89 फीसदी या 201.05 अंक की वृद्धि के साथ 22,821.40 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा का शेयर सबसे ज्यादा 4.07 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ।

रीपो रेट पर आज आरबीआई करेगा फैसला

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की तीन दिवसीय मीटिंग की शुरुआत बुधवार को शुरू हुई। ऐसा माना जा रहा है कि एमपीसी प्रमुख ब्याज दर यानी रीपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। चुनाव नतीजे आने के बाद अब बाजार की नजर आरबीआई की एमपीसी बैठक के नतीजों पर है, जिसकी घोषणा शुक्रवार (7 जून) को होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर (रीपो) में कटौती करने की उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि मुद्रास्फीति को लेकर चिंता अब भी बरकरार है। अगर आरबीआई रीपो रेट में कटौती करता है तो लोन की ईएमआई कम हो सकती है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को होगा।

गर्मी के बीच कोला, आइसक्रीम की बिक्री में जोरदार उछाल

नईदिल्ली। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच कोला, पेय पदार्थ, आइसक्रीम सहित गर्मी से राहत प्रदान करने वाले अन्य उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। पेप्सिको इंडिया और कोका कोला जैसे पेय पदार्थ विनिर्माताओं ने कहा कि पूर्वी, उत्तर और मध्य भारत में मांग में भारी उछाल आया है। कंपनियों ने मांग में भारी बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए अपना भंडार (इन्वेंट्री) बढ़ा लिया है। उत्पाद ई-वाणिज्य सहित खुदरा मंच पर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हों यह सुनिश्चित किया जा रहा है। पेप्सिको इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, ''देशभर में तापमान बढ़ने से लोग गर्मी से राहत प्रदान करने वाले पेय पदार्थों की तलाश कर रहे हैं।'' कोका-कोला इंडिया ने कहा कि गर्मी के मौसम के चरम पर पहुंचने के साथ ही भारतीय पेय बाजार में मांग में उल्लेखनीय तेजी आई है। कोक, थम्सअप, माज़ा, स्प्राइट और मिनट मेड बनाने वाली इस कंपनी की बिक्री में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।

एनवीडिया बनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी

नईदिल्ली। अमेरिका की कंप्यूटर-चिप कंपनी एनवीडिया कॉर्प दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कंपनी का मार्केट कैप बुधवार को 3.01 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मार्केट कैप के मामले में एनवीडिया कॉर्प ने आईफोन मेकर एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि एप्पल के शेयरों में 0.8% की बढ़ोतरी हुई और इसका मार्केट कैप 3.003 ट्रिलियन डॉलर हो गया। सांता क्लारा, कैलिफ़ोर्निया स्थित कंपनी के शेयरों में इस साल लगभग 147 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। इस वजह है कि आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस टास्क्स को शक्ति देने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिप्स की मांग आसमान छू रही है। बुधवार को, शेयर 5.2 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 1,224.40 डॉलर पर बंद हुए, जिससे बाजार मूल्य 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया।

आरबीआई की मौद्रिक नीति की पिच का आकलन कितना जरूरी

तमाल बंद्योपाध्याय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति को क्रिकेट मैच की तरह समझने की कोशिश करते हैं। छह सदस्यों वाली आरबीआई की दर निर्धारण करने वाली समिति, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) एक टीम की तरह है और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास इसके कप्तान हैं।

टेस्ट मैच से पहले कप्तान पिच का बारीकी से निरीक्षण करता है ताकि खेलने की रणनीति बनाई जा सके। हरी पिच पर खेलना, समतल पिच या सूखी पिच पर खेलने से काफी अलग होता है। इसी तरह धूल भरी पिच, कप्तान को कुछ अलग करने का विचार देती है। इसमें मौसम भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीम जब हवा वाले मौसम में क्रिकेट खेलती है या फिर ज्यादा धूप वाले दिन खेलती है, तब भी उसमें फर्क होता है। इसी तरह जानते हैं कि ताजा नीति के लिए पिच कैसी है? और मौसम कैसा है?

शेयर बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं और यही बात सोने की कीमतों पर भी लागू होती है। बॉन्ड प्रतिफल भी शीर्ष स्तर के मुकाबले निचले स्तर पर पहुंच गया है। (बॉन्ड कीमतें और प्रतिफल दोनों ही अलग दिशा में जा रहे हैं) 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल 7 प्रतिशत के करीब है और यह 7.62 प्रतिशत के शीर्ष स्तर से नीचे हैं। जब मौद्रिक नीति का मैच इस तरह की पिच पर खेला जाता है तब इसके नतीजे का अनुमान लगाना आसान है। यह पहली बार है जब आम चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद, आरबीआई की नीतिगत बैठक हो रही है। अप्रैल की शुरुआत में रिजर्व बैंक के 90वें वर्षगांठ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'मैं अगले 100 दिनों तक चुनाव में

व्यस्त हूं। आपके पास अभी सोचने के लिए पर्याप्त समय है। शपथ लेने के बाद आपके पास बहुत काम होगा।'

प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि आरबीआई के मुद्रास्फीति के लक्षित रूपरेखा के चलते मूल्य दबाव को संयमित करने में मदद मिली है। केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति और वृद्धि में संतुलन बनाने जैसे 'अनूठे उपायों?' पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'अगले दशक में, आरबीआई को सबसे अधिक प्राथमिकता वृद्धि को देनी चाहिए, साथ ही भरोसे को बनाए रखने और स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए।'

वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल की पहली मौद्रिक नीति में कोई हैरान करने लायक बात नहीं हुई। एमपीसी ने लगातार आठवीं बैठक में रीपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। इसके अलावा नीतिगत रुख में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इसमें 'बाजार से पूंजी आपूर्ति कम करने का रुख' बना रहा। भारतीय केंद्रीय बैंक की दर निर्धारण समिति के छह सदस्यों में से पांच ने नीतिगत दर और रुख दोनों की यथास्थिति के लिए मतदान किया।

फरवरी के अनुमानों में, वित्त वर्ष 2025 में आरबीआई की वृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7 प्रतिशत और सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया था। आरबीई ने फरवरी में कहा था कि वृद्धि और मुद्रास्फीति दोनों अनुमानों के जोखिम समान रूप से संतुलित थे। सवाल यह है कि आखिरी मौद्रिक नीति के बाद से क्या बदला है? वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी के साथ-साथ ब्याज दरों में कटौती की बात अब खत्म हो गई है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने अप्रैल में मुख्य पुनर्वित्त परिचालन के ब्याज दर और सीमांत उधार सुविधा तथा जमा सुविधाओं पर ब्याज दरों को क्रमशः 4.50 प्रतिशत, 4.75 प्रतिशत और 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा था और संभावना है कि मई में मुद्रास्फीति में वृद्धि के बावजूद 6 जून को दर में कटौती की जाएगी। लेकिन बाजार को आने वाले महीने में दरों में लगातार कटौती की उम्मीद नहीं है बल्कि उन्होंने इस साल सिर्फ एक और कटौती पर दांव लगाने की उम्मीदें कम कर दी हैं। साल की शुरुआत में छह कटौती तक की उम्मीदें थीं।

क्रमशः ...

छग में भाजपा ने कांग्रेस के बड़े-बड़े सूरमा को चूरमा बना दिया- साय

रायपुर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े-बड़े सूरमा को हमारे प्रत्याशियों ने चूरमा बना दिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को पटखनी देकर और चार-चार पूर्व मंत्रियों को हराकर हमारे प्रत्याशी आए हैं। मैं सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। चुनाव में जनता के आशीर्वाद से मिली ऐतिहासिक जीत के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जिस पर हम सबको खरा उतरना है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उक्त बातें कही और छत्तीसगढ़ के सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली और केंद्र में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता की मुहर है। इस ऐतिहासिक परिणाम के लिए प्रदेश की जनता को धन्यवाद, बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री साय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए कहा कि तपती गर्मी में पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक एवं सदस्यों के कठिन परिश्रम की बदौलत हमें ऐतिहासिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके लिए सभी को बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। पड़ोसी राज्य झारखंड और ओडिशा की जीत का श्रेय राज्य के मंत्रियों, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को देते हुए उन्होंने कहा कि सबके अथक मेहनत से हमनें दोनों राज्यों में भाजपा का परचम लहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने 54 सीटों के साथ 46 प्रतिशत वोट प्राप्त किये थे और अब लोकसभा चुनाव में 6 प्रतिशत वोटों की वृद्धि हुई है, जिससे कि 68 विधानसभा सीटों में हमें जीत प्राप्त हुई है। इस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार है और अब लोकसभा में जनता ने प्रचंड जीत दिलाकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड में भाजपा की जीत पर उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में आयोजित जनसभा के दौरान मुझे मंच में आधे से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के नेताओं की मौजूदगी नजर आती थी। सबके प्रयासों से दोनों राज्यों में भाजपा इस मुकाम पर पहुंची है।

विष्णु देव साय ने कहा कि ओडिशा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ हमारी सरकार बन रही है। राज्य में लोकसभा और विधानसभा के ऐतिहासिक जनादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मुहर लगायी है। वहां 25 साल सत्ता में रहे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दोनों सीट में हराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है।

अब हमें केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाना है - देव- भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय के एक्जिट पोल में भाजपा को कम सीटे मिलती बताई जा रही थी, लेकिन प्रदेश की जनता ने भाजपा को अपना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद देते हुए प्रदेश की 54 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार बनाने का जनादेश दिया। श्री देव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान किए अपने सभी वादों को प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तेजी के साथ पूरा कर रही है। अब हमें केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाना है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी मिल सके। श्री देव ने कहा कि पहले मिथक बन चुका था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ बन गया है लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम और छत्तीसगढ़ की जनता ने उस मिथक को तोड़ दिया और भाजपा अब पंचायत, नगरीय निकाय सहित विधानसभा एवं लोकसभा मैं भी अपना परचम लहरा रही है। श्री देव ने चुनाव प्रबंधन समिति के सभी लोगों को कुशल चुनाव प्रबंधन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएँ दी है।

मोदी के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत सरकार देश को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी - जम्वाल- क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने चुनाव प्रबंधन समिति को संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को अर्जित सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि आप सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने चुनाव में जो अनथक परिश्रम किया है, यह सब उसी का प्रतिफल है। आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम सब एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बनाने में सफल हुए हैं। श्री जम्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए देश विरोधी ताकतों ने तो जी-तोड़ कोशिशें खूब की लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आगे वे ताकतें सफल नहीं हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर देश तेजी से विकास करेगा और एनडीए की मजबूत सरकार देश को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक शिवरतन शर्मा ने चुनाव प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव की सफलता के लिए 38 प्रकार की समितियाँ बनाई थीं और चुनाव में उन समितियों ने पूरे समर्पण के साथ काम करके प्रदेश की 11 में से 10 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित की। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिया गया लक्ष्य लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्राप्त किया है। हमें 51 प्रतिशत वोट पाने का लक्ष्य दिया गया था और आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमने छत्तीसगढ़ में 52.5 प्रतिशत वोट प्राप्त किया यानी कि विधानसभा चुनाव से 6 प्रतिशत ज्यादा वोट भाजपा को प्राप्त हुआ। कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशी 2018-23 के बीच मंत्री रहे, वे भी लोकसभा चुनाव में पराजित हुए।

जानकारी गलत निकली तो पैसा मिलना हो जायेगा बंद,वसूली भी होगी

महतारी वंदन योजना का लाभ ले रहे लोगों की होगी जांच

रायपुर। गलत जानकारी देकर यदि महतारी वंदन योजना का लाभ ले रहे हैं तो सतर्क हो जाएं अब विभाग जांच करवा रही है और अपात्र रहे तो बंद हो जायेगा पैसा मिलना। महिला व बाल विकास विभाग ने महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों की पात्रता फिर से जांचने की तैयारी कर ली है। जांच में गलत तरीके से योजना का लाभ लेना पाए जाने पर अपात्र हितग्राहियों से राशि की वसूली भी होगी।

विभाग ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाने का निर्णय लिया है जिसमें योजना का लाभ अपात्र महिलाओं के द्वारा लिए जाने की बात सामने आई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शासकीय सेवा में पदस्थ, सेवानिवृत्त या पेंशन का लाभ ले रहीं बहुत सी महिलाओं ने आवेदन किया और उनमें से कई महिलाएं योजना से लाभान्वित भी हो रही हैं।

ऐसे भी मामले आए हैं, जिनमें एक ही आवेदक ने दो-दो आवेदन किए और दोनों ही स्वीकृत हो गए हैं। ऐसी महिलाओं के खाते में दो-दो बार राशि हस्तांरित हो रही है। ऐसे अधिकतर मामलों में आवेदकों ने स्वयं के अलावा अपने पति या स्वजन का भी आधार कार्ड नंबर आवेदन में लगाया था।

सत्यापन के दौरान यह पकड़ में नहीं आया। विभाग एक नाम वाले 20 हजार से अधिक आवेदनों की जांच कर रहा है। इनमें नाम, पता, जन्मतिथि समान हैं।

योजना के लिए 70.26 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 70.14 लाख महिलाओं को पात्र माना गया। 11,771 आवेदन रिजेक्ट हुए थे। पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह एक-एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक चार किस्तों में 2,500 करोड़ से अधिक की राशि जारी हो चुकी है।

हितग्राहियों के आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी

महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने वालों की जांच कराई जाएगी। अधिकारियों को पारदर्शिता के निर्देश दिए गए हैं। हितग्राहियों के आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

वट सावित्री पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में सुहागन महिलाओं ने की वटवृक्ष की पूजा-अर्चना

रायपुर। वट सावित्री व्रत के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय की अगुवाई में दर्जन भर महिलाओं ने पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर सुहागन महिलाओं ने बरगद के पेड़ की विधि-विधान पूर्वक पूजा-अर्चना करते हुए वटवृक्ष की परिक्रमा की और अपने-अपने पति की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। पूजा के दौरान महिलाओं ने सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनी। पूजा-अर्चना के बाद श्रीमती कौशल्या साय ने सभी सुहागन महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व पति-पत्नी के बीच अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

जीएसटी के संयुक्त आयुक्त ने ली ट्रांसपोर्टरों की बैठक

रायपुर. इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत आज जीएसटी संभाग दो रायपुर ने ट्रांसपोर्टरों की बैठक ली, जिसमें संयुक्त आयुक्त सीआर महिलांगे ने हाल ही में लागू किए गए ई वे बिल से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी. बैठक में बताया गया कि ई-वे बिल का निर्माण क्रेता एवं विक्रेता व्यवसाइयों के साथ-साथ विभिन्न परिस्थितियों में ट्रांसपोर्टर भी जारी कर सकते हैं. बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से आए ट्रांसपोर्टरों ने ई वे बिल से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को रखा. संयुक्त आयुक्त महिलांगे ने आश्वासन दिया कि यथासंभव समस्याओं का निदान किया जाएगा. इस अवसर पर उपायुक्त मुकेश त्यागी, सहायक आयुक्त अवधेश यादव उपस्थित थे. उपायुक्त त्यागी ने ई वे बिल निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का विस्तार से ट्रांसपोर्टरों को जानकारी दी. ई वे बिल निर्माण के समय किन-किन प्रकार की गलतियों की संभावना रहती है और ई वे बिल के समय कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इस संबंध में त्यागी ने विस्तार से बताया. इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत् जीएसटी विभाग ई वे बिल निर्माण से संबंधित जागरूकता अभियान जोर-शोर से चला रहा है.

हसदेव अरण्य में रोक के बावजूद हो रही जंगल की कटाई, डॉ. महंत

रायपुर। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को पत्र लिख कर हसदेव अरण्य कोल फील्ड के सभी कोल ब्लॉक से उत्खनन एवं वृक्षों के विरोहन की गतिविधियों को रोक लगाने एवं कूट रचित उत्तरदायित्व व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद करने के निर्देश देने आग्रह किया है. डॉ. चरणदास महंत ने पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने परसा कोल ब्लॉक में उत्खनन के लिए आवश्यक अनुमतियां हासिल करने के लिए फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव पास करने की ग्रामीणों के आरोपों की जांच की हैं. इस जांच में आयोग ने ग्राम सभा की फर्जी कार्यवाही के आरोपों को प्राथमिक रूप से सही पाते हुए परसा कोल ब्लॉक में खनन के लिए कोई भी अग्रिम कार्यवाही न करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश 30 मई 2024 को किया है. आदेश की प्रति संलग्न है.ग्राम सभाओं की बैठकों में प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना तथा प्रस्ताव पारित हुए बिना ही कूट रचना करके कार्यवाही विवरणों में प्रस्ताव पारित होने का उल्लेख करना गंभीर आपराधिक मामला है, जिसे षड्यंत्रपूर्वक अंजाम दिया गया है. इस कूट रचित कार्यवाही विवरण के कारण ही 02.02.2022 के भारत सरकार की ओर से कोल ब्लॉक आवंटन रकबा 1136 हेक्टेयर (ग्राम परसा तथा केते) के लिए अनुमतियां दी गई.

लोस चुनाव की आचार संहिता खत्म चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश

रायपुर। लोकसभा चुनाव 2024 की वजह से देश में लागू आदर्श आचार संहिता आज से समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि इस वर्ष देश में सबसे लंबे समय तक आदर्शन संहिता लागू रहा।

विधायक साहू और मरावी को किया रोगी पशु कल्याण समिति का सदस्य मनोनीत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू एवं प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी को राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय रायपुर के रोगी पशु कल्याण समिति का सदस्य मनोनीत किया है। यह समिति पशुधन के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करती है। जिसका उद्देश्य पशुधन को उसका सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का हक प्रदान करना है।

राज्य के 362 हाजी सफर-ए-हज के लिए हुए रवाना

रायपुर। हज 2024 के लिए मुंबई के अंतराष्ट्रीय विमानतल से सउदी एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर एसवी 3629 से छत्तीसगढ़ राज्य के 362 हाजियों का जत्था दिनांक 06/06/2024 को संध्या 06.40 बजे, हज के लिए रवाना हुआ। जिसमे 190 पुरुष एवम 172 महिला हज यात्री शामिल रहे। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों की दिनांक 4/6/2024 को हज हाउस में रिपोर्टिंग कराई गई, दिनांक 05/06/2024 को हज यात्रा के दस्तावेजों का वितरण किया गया। 06/06/2024 को प्रातः 10.00 बजे से विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। एयरपोर्ट पर भी हज यात्रियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जिससे हज यात्रियों का प्रस्थान सुगमता पूर्वक संपन्न हुआ। मुंबई एंबारकेशन प्वाइंट से राज्य के हज यात्रियों की सुगमता पूर्वक प्रस्थान की समस्त व्यवस्थाओं का संपादन छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान, हज कमेटी के कार्यपालन अधिकारी सचिव डा. साजिद अहमद फारूकी, हज कमेटी के सदस्य, मोहम्मद इमरान, हाजी अब्दुल रज्जाक खान, मौलाना कारी अशफाक अहमद अंजुम, शमीम अख्तर, एवम अन्य माननीय सदस्यगण, राज्य हज कमेटी के कर्मचारी सैयद सलीम अशरफ, मोहम्मद हुसैन मलकानी, राजिक अमजद एवम अन्य द्वारा किया गया।

सरकारी स्कूलों में भी होंगे पैरेंट्स मीटिंग, आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा में सुधार के संदर्भ में एक बड़ी खबर आ रही है। विष्णुदेव सरकार ने प्रायवेट स्कूलों सरीखा सरकारी स्कूलों में पैरेंट्स मीट आयोजित करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, इससे पहले कई बार पैरेंट्स मीट करने पर विचार हुआ। पिछली सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग ने भी सरकारी स्कूलों में पैरेंट्स मीट शुरू करने का प्रयास किया था। मगर इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। मगर विष्णुदेव सरकार ने अब इसका आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टरों को सुनिश्चित करने कहा है कि पैरेंट्स मीट में कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने पैरेंट्स मीट करने के फायदे भी गिनाए हैं। मसलन, बच्चों के शरीरिक, मानसिक विकास के लिए पालकों और स्कूलों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। बच्चों के संपूण गतिविधियों से पालकों को अवगत कराने से उन्हें बेहतर मार्गदर्शन और प्रेरणा मिल सकती है। शिक्षकों और पालकों के संपूर्ण प्रयास से बच्चां की पढ़ाई के प्रति साकारात्मक वातावरण बनेगा। बच्चों की काउंसलिंग से उन्हें परीक्षा का तनाव नहीं रहेगा और स्कूलों से ड्रॉप आउट याने पढ़ाई छोड़ देने से रोकने में पालकों की भूमिका सुनिश्चत करना।

छत्तीसगढ़ सस्टनेबिलिटी एंड रिजनरेटिव डेव्हलपमेंट के मामले में बनेगा अग्रणी राज्य

रायपुर। सस्टनेबिलिटी एंड रिजनरेटिव डेव्हलपमेंट के मामले में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने आज राज्य नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने अपने विचार रखे। नया रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में हुई इस बैठक में सदस्यों ने इस विषय पर के लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सुझाव दिए।

गौरतलब है कि विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर 2024 तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव एवं सदस्य के. सुब्रमण्यम, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत और मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ धीरेंद्र तिवारी ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु ,मध्यम एवं दीर्घकालिक विजन एवं रणनीतियों पर सुझाव दिए। वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले टिकाऊ सोसाइटी, विभिन्न सूचकांकों, एसडीजी सूचकांक, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, कार्बन फुटप्रिंट, कृषि, वानिकी, राज्य में स्थापित उद्योगों, भूमि, वायु, जल, अपशिष्ट और ऊर्जा पर प्रभाव का आंकलन, प्रौद्योगिकी संचालित अनुसंधान एवं विकास, सरकारी वित्त पोषण और निजी पूंजी निवेश, जागरूकता और संवेदनशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, लोक कल्याण में वृद्धि सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव और सदस्य के. सुब्रमण्यम ने कहा कि हमेंअब सतत विकास के साथ साथ पुर्नयोजित विकास पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि दिनों दिन वन कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण वनोपज का उत्पादन कम होते जा रहा है, जो चिंता का विषय है, वन महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो विशेष ध्यान देने का विषय है।

वनों के संरक्षण के लिए हमें स्पष्ट रोड मैप बनाने की जरूरत है। नदियों के आसपास लगातार माइनिंग हो रहा है जो चिंता का विषय है। हमें ग्रास लैंड को बचाना होगा इससे इकोसिस्टम बेहतर होगा और जैव विविधता संरक्षित होगी। हमें नवीकरण ऊर्जा पर ध्यान देना होगा।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा

रायपुर। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के निर्देशानुसार रिट, क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, अवमानना प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का चिन्हांकन कर सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। प्रकरणों का भौतिक सत्यापन जिला न्यायालय बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग में, पदस्थ, 40 न्यायिक अधिकारियों एवं उच्च न्यायालय स्थापना में पदस्थ लगभग 36 अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य के 21 वें दिन आज गुरूवार को मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपरोक्त कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इसके दौरान मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय में चल रहें उच्च न्यायालय के भवन के आधारभूत संरचना के नवीनीकरण के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में 13 मई से 07 जून 2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है, इस दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन, निराकृत प्रकरणों का डिजीटल माध्यम अर्थात् स्केंनिग उपरान्त भौतिक सत्यापन, एवं उच्च न्यायालय के भवन के आधारभूत संरचना के नवीनीकरण के कार्यों को किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित करने की प्रणाली विकसित किया गया है ताकि ऐसे उपरोक्त चिन्हांकित लंबित प्रकरणों को सुनवाई पश्चात् निराकृत किया जा सके।-

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.